Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Thursday, 19 December 2024 ● Year : 02 ● Issue : 326 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

उन लोगों पर ध्यान न दें, जो आपको भयभीत और दुखी करते हैं, जो आपको बीमारी और मृत्यु की ओर ले जाते हैं।

-रूमी

Nothing Just Shraddha...

SHARE

सेंसेक्स	:	80,684.45
निफ्टी	:	24,336.00

SARAFA

सोना	:	7,330
चांदी	:	100.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

दम घुटने से दो बच्चों सहित छह लोगों की चली गई जान

JAMMU : बुधवार को जम्मू कठुआ स्थित शिवानगर शहर में दुखद हादसे में छह लोगों की जान चली गई। कठुआ के जीएमसी अस्पताल के चिकित्सक के मुताबिक घर में आग लग गई थी, जिसमें दम घुटने से सभी की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे। कठुआ जीएमसी अस्पताल के डॉ. सुरिंदर अत्री ने कहा, यह एक दुखद घटना है। यह आग रेंटेड हाउस में लगी है। हमारे असिस्टेंट मैट्रन तीन चार महीने पहले रिटायर हुई थीं। किराए के मकान में ही यह घटना घटी। इस घटना में कुल छह लोगों की जान चली गई। बचे हुए तीन लोग अभी खतरे से बाहर हैं।

29 दिसंबर से शुरू होगा 'उद्यान उत्सव'

NEW DELHI : बुधवार को राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति निलयम, बोलारम, सिकंदराबाद 29 दिसंबर से 15 दिवसीय पुष्प एवं बागवानी महोत्सव उद्यान उत्सव की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) हैदराबाद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित उद्यान उत्सव का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्रकृति का जश्न मनाना, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना है। लोग विषयगत स्टालों पर जाकर और कार्यशालाओं में भाग लेकर कृषि और बागवानी में नवाचार और तकनीकी विकास के बारे में खुद को जागरूक कर सकते हैं।

सैन्य अभ्यास के दौरान ब्लास्ट, दो जवानों की मौत

JAIPUR : बुधवार को राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में सैन्य अभ्यास के दौरान तोप से फायर करते समय हुए ब्लास्ट में दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को सूरतगढ़ के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह हादसा चार्ली सेंटर पर उस वक्त हुआ जब सैनिक गोला-बारूद लोड कर रहे थे। चार्जर में अचानक विस्फोट होने से तीन जवान इसकी चपेट में आ गए।

उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

NEW DELHI : दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी, 2020 के दंगों से जुड़े साजिश मामले में आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को सात दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी।

अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

AGENCY NEW DELHI : बुधवार को भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टेस्ट सीरीज के ड्रा रहे तीसरे मैच के बाद अश्विन ने यह फैसला लिया। एडिलेड में खेला गया डे-नाइट टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच था। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 106 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 24 की औसत से 537 विकेट लिए। अश्विन ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारत के पहले तीन टेस्ट मैचों में से सिर्फ एक ही टेस्ट (डे-नाइट टेस्ट) खेला, जिसमें उन्होंने 53 रन देकर एक विकेट लिया था। इससे पहले अश्विन भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, जहां भारत को 0-3 से करीब शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उस सीरीज में अश्विन का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 41.2 की औसत से सिर्फ नौ विकेट लिए थे।

अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

इंटरनेशनल करियर

टेस्ट

मैच	विकेट	रन
106	537	3503

वनडे

मैच	विकेट	रन
116	156	707

टी-20i

मैच	विकेट	रन
65	72	184

एडिलेड में खेला गया डे-नाइट मैच था उनका आखिरी टेस्ट मैच

116 वनडे मैच में लिए 156 विकेट

अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो उनके नाम 116 मैचों में 33 की औसत और 4.93 की इकॉनमी से 156 विकेट हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/25 रहा है। उन्होंने वनडे में एक अर्धशतक की मदद से 707 रन बनाए हैं जबकि टी20 में उन्होंने 65 मैचों में 6.90 की इकॉनमी और 23 की औसत से 72 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 का रहा है।

दुनिया के 11वें ऑलराउंडर

अश्विन के नाम छह टेस्ट शतक और 14 अर्धशतकों के साथ 3503 टेस्ट रन भी हैं और वह 300 विकेट और 3000 रन का डबल करने वाले दुनिया के सिर्फ 11वें ऑलराउंडर हैं। उनके नाम मुथैया मुरलीधरन के बराबर सर्वाधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड हैं।

सुप्रीम कोर्ट में होगी झारखंड में कोयला चोरी मामले की सुनवाई

PHOTON NEWS RANCHI : सुप्रीम कोर्ट में धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है। इस मामले में सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था।

3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन का पीएम ने दिया जवाब

कांग्रेस ने वर्षों तक अंबेडकर व एससी एसटी समुदाय को किया अपमानित

AGENCY NEW DELHI : बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका पारिस्थितिक तंत्र दुर्भावनापूर्ण झूठ से कई वर्षों के अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी-एसटी समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह के मंगलवार को राज्यसभा में दिए गए एक बयान को कांग्रेस ने संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है। इसके चलते पार्टी के सदस्यों ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और कामकाज नहीं होने दिया।

अंबेडकर के विचारों के अनुसार गरीबों के लिए अपनी सरकार के काम का किया दावा

25 करोड लोगों को गरीबी से निकाला

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने का अथक प्रयास कर रही है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकलना एसटी-एसटी अधिनियम को मजबूत करना, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और जितनी भी योजनाएं हैं उन्होंने गरीब और हाशिए पर गए लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को किया उजागर

प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने डॉ. अंबेडकर का अपमान करने और एससी-एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से वे स्पष्ट रूप से स्तब्ध हैं, यही कारण है कि वे अब नाटकीयता में लिप्त हैं! दुख की बात है कि उनके लिए लोग सच्चाई जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर चरणबद्ध पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस के पापों की सूची में कई विशेष शामिल हैं।

खड़गे ने गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा

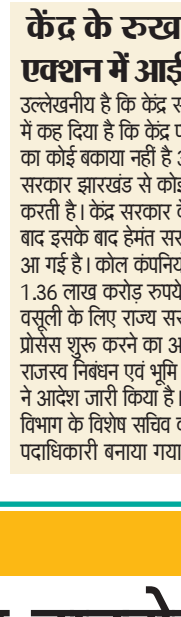

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में खड़गे ने कल सदन में संविधान पर बहस के दौरान शाह द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने (अमित शाह) विपक्षी सदस्यों से कहा था कि जितनी बार वे (विपक्षी सदस्य) बाबा साहेब का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार वे भगवान का नाम लेंगे तो उन्हें सात बार स्वर्ग मिलेगा। खड़गे ने कहा कि इससे पता चलता है कि गृहमंत्री खुद अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी से पूरे देश में गुस्सा फैल सकता है, क्योंकि कोई भी अंबेडकर और देश के संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

मेरे बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया : शाह

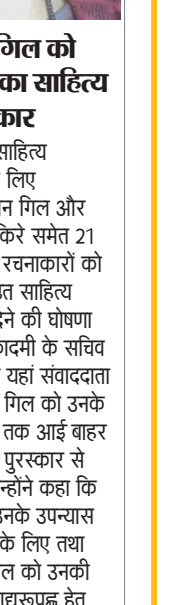

बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और कहा कि वह सपने में भी संविधान निमार्ता का अपमान नहीं कर सकते हैं। शाह ने यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कल से कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता उपस्थित थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाजपा के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर भाजपा के वक्ताओं ने उदाहरण के साथ अपने विचार रखे।

किसानों ने किया तीन घंटे का 'रेल रोको' प्रदर्शन

CHANDIGADH : फसलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को किसानों के रेलमार्गों पर बैठ जाने के कारण पंजाब में ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। 'रेल रोको' आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने किया है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कई स्थानों पर रेल पटरियों पर बैठे रहे । गुरदासपुर के मोगा, फरीदकोट, कादियां और बटाला; जालंधर में फिल्लौर; होशियारपुर में टांडा, दसूया, माहिलपुर; फिरोजपुर में मक्खू, तलवंडी भाई; लुधियाना में साहनेवाल; पटियाला में शंभू; मोहाली, संगरूर के सुनाम और लहरा, बठिंडा के रामपुरा फूल और अमृतसर के देवीदासपुरा समेत कई स्थानों पर प्रदशनकारी किसानों ने ट्रेन मार्गों को बाधित किया। जम्मू से सियालदह जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस, अमृतसर से मुंबई जाने वाली दादर एक्सप्रेस और नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस को लुधियाना रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर रोक दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र को कई बार दिया गया बकाया राशि का विस्तृत ब्रेकअप

केंद्र सरकार के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये पर झारखंडियों का हक : हेमंत सोरेन

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्र सरकार की ओर से 1.36 लाख करोड़ झारखंड के बकाया को देने से इनकार करने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंडियों के हक में 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया राशि का एक-एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। फिर भी केंद्र सरकार के जरिए इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है।

- हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है इसे नकारना
- अधिकारियों को सीएम ने बकाया वापसी के लिए लीगल प्रोसेस शुरू करने का दिया है आदेश
- भू-राजस्व विभाग के विशेष सचिव को बनाया गया है नोडल पदाधिकारी

हम इसे होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ह्यएक्सह्न पर बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि झारखंड भाजपा यदि इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ आवाज बुलंद नहीं करती है तो यह साफ माना जाएगा कि इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है।

केंद्र के रुख के बाद एक्शन में आई सरकार

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लोस में कह दिया है कि केंद्र पर झारखंड का कोई बकाया नहीं है और केंद्र सरकार झारखंड से कोई भेदभाव नहीं करती है। केंद्र सरकार के इस रूप के बाद इसके बाद हेमंत सरकार एक्शन में आ गई है। कोल कंपनियों के यहां 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार ने लीगल प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। भू-राजस्व विभाग के विशेष सचिव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

हिंदी में गगन गिल को मिलेगा 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार

NEW DELHI : साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए प्रतिष्ठितकवयित्री गगन गिल और अंग्रेजी में ईस्टरिन किरे समेत 21 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा बुधवार को की। अकादमी के सचिव के. श्रीनिवास राव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित जाएगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में किरे को उनके उपन्यास ह्यस्पिरिट नाइट्सह्न के लिए तथा मराठी में सुधीर रसाल को उनकी आलोचना ह्यविंदांचे गुद्यरूपह्न हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विजेता रचनाकारों को अगले साल आठ मार्च को आयोजित एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिसमें एक लाख रुपये की राशि, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और शॉल शामिल है। राव के मुताबिक, इनके अलावा संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा (कविता संग्रह), राजस्थानी में मुकुट मणिराज (कविता संग्रह), पंजाबी में पॉल कौर (कविता संग्रह), कश्मीरी में सोहन कौल (उपन्यास) और गुजराती में दिलीप झावेरी (कविता संग्रह) समेत अन्य को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अकादमी ने फिलहाल 21 भाषाओं के लिए पुरस्कारों का ऐलान किया है जिनमें आठ कविता संग्रह, तीन उपन्यास, दो कहानी संग्रह, तीन निबंध, तीन साहित्यिक आलोचना, एक नाटक और एक शोध की पुस्तक शामिल हैं।

बांग्लादेश की सीमा पर दिखे यूएवी, वायु सेना ने लड़ाकू विमानों से बढ़ाई निगरानी

AGENCY NEW DELHI : बांग्लादेश सीमा पर मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के देखे जाने के बाद मेघालय पुलिस की ओर से सतर्क किए जाने पर वायु सेना ने अपनी निगरानी गतिविधि बढ़ा दी है। राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा और शेला के पास बेराकटार टीबी-2 मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के देखे जाने के बाद भारतीय राडार और लड़ाकू विमान नियमित रूप से इन पर नजर रख रहे हैं। मेघालय सीमा के बहुत नजदीक एक बांग्लादेशी ड्रोन के देखे जाने के बाद निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने पर बांग्लादेशी यूएवी को मार गिराया जाएगा। भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पिछले हफ्ते में कई बार टीबी-2 यूएवी देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश में छतक और सुनामगंज के आस-पास के इलाकों में यूएवी उड़ते हुए पाए गए। इसके अलावा सीमा के पास मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा और शेला के पास बेराकटार टीबी-2 मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को उड़ते हुए देखा गया है।

एयरबेस से यूएवी का संचालन

बांग्लादेश ने इस साल की शुरूआत में अपने सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत यह ड्रोन हासिल किए थे। बांग्लादेश के तेजगांव एयरबेस से एक यूएवी संचालित किया गया था। तुर्की कंपनी बायकर ने बेराकटार टीबी-2 यूएवी को विकसित किया है, जिसे निगरानी और सटीक हमला मिशनों में अपनी दोहरी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये यूएवी 300 किमी. की परिचालन सीमा और 27 घंटे की धीरज के साथ अपनी तरह के सबसे उन्नत में से हैं। सीमा पर टीबी-2 यूएवी देखे जाने की जानकारी मिलने पर मेघालय पुलिस के महानिदेशक इदाशीशा नोंग्रांग ने इस घटना के बारे में भारतीय वायु सेना को भी अवगत कराया।

हर स्थिति पर सेना की बारीक नजर

सुरक्षाबलों ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अक्सर पड़ोसियों के लिए सीधे सुरक्षा खतरा पैदा करने के बजाय आंतरिक समर्थन जुटाने का काम करती हैं। भारत सीमा पर निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को बढ़ाकर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारतीय सशस्त्र बल अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभावित जवाबी उपायों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। बांग्लादेशी सेना के टीबी-2 हमलावर ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ को भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट उड़ने वाली किसी भी हवाई वस्तु को मार गिराने का निर्देश दिया गया है, इसीलिए भारतीय राडार और लड़ाकू विमान नियमित रूप से इन ड्रोन पर नजर रख रहे हैं।

बड़ी संभावना — पत्थरों के नीचे दबे स्रोतों में उपलब्ध है भविष्य का बड़ा खजाना

बिजली आपूर्ति में सक्षम है धरती के गर्भ में छिपा हाइड्रोजन

AGENCY NEW DELHI : हमारे रोजाना के जीवन में विज्ञान और तकनीक से प्राप्त सुविधाएं कई समस्याओं का समाधान करती हैं। समस्याओं के निदान में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार रिसर्च में विशेषज्ञ लगे हुए हैं। रिसर्च से आ रही नई जानकारी में भविष्य के लिए तमाम अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस पृथ्वी के गर्भ में छिपी संभावनाओं पर रिसर्च कर रहे विशेषज्ञों ने बड़ी जानकारी दी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यह जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पानी नहीं बन सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पृथ्वी पर पानी का निर्माण करते हैं। अगर यह पानी न बने तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लंबे समय से चल रहे रिसर्च में अब जाकर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे हाइड्रोजन का खजाना मौजूद है। इसका मात्र दो फीसद हिस्सा ही पूरी धरती पर 200 साल तक बिजली की आपूर्ति कर सकता है। ये हाइड्रोजन पत्थरों और जमीन के नीचे स्रोतों में विद्यमान है।

जमीन की सतह के नीचे करीब 6.3 लाख करोड़ टन हाइड्रोजन है मौजूद

अभी इस हाइड्रोजन के सटीक स्थान का पता लगाने में लगे हैं वैज्ञानिक

- पृथ्वी में मौजूद तेल से 26 गुना अधिक है इसकी मात्रा
- अत्यंत कम होती है वायुमंडल में विद्यमान हाइड्रोजन की मात्रा

जल्द सार्वजनिक होगी विस्तृत जानकारी

वैज्ञानिकों को अभी इस हाइड्रोजन के सटीक स्थान का पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने धरती में मौजूद हाइड्रोजन की जानकारी देते हुए बताया है कि सटीक स्थान की खोज पर शोध जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस खजाने की विस्तृत जानकारी सामने आ जाएगी।

शनि ग्रह के छल्लों की उम्र पर हो रहा रिसर्च

सौरमंडल के शनि ग्रह के छल्लों पर भी रिसर्च जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के चमकीले छल्ले करीब 4.5 अरब साल पुराने हैं। हाल ही में जापानी वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह दावा किया। अब तक किए गए शोध में शनि के छल्लों को 10 करोड़ से 40 करोड़ साल पुराना बताया गया था।

वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के छल्लों की उम्र हमारी सोच से कहीं अधिक हो सकती है। नासा के कैसिनी मिशन के डाटा के आधार पर इसका दावा किया गया है।

सौरमंडल का प्रारंभिक समय

वैज्ञानिकों ने कहा कि शनि के छल्ले पर धूल की परत न होने के कारण उन्हें साफ देख सकते हैं।?जब रेत के कणों से भी छोटे कण छल्लों की बर्फ से टकराते हैं, तो वह वाष्प बन जाते हैं। इसी वजह से छल्ले हमेशा साफ रहते हैं। जापानी वैज्ञानिक ह्योडो ने बताया है कि भले ही छल्ले करीब 2.25 अरब साल पहले बने हों, लेकिन संभावना है कि ये सौरमंडल के शुरूआती समय में ही बन गए थे।

BRIEF NEWS

डहरे टुसु में पुरुलिया से शामिल होंगे हजारों संस्कृति प्रेमी

JAMSHEDPUR : वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा 5 जनवरी को डिमना से साकची के आमबगान मैदान तक डहरे टुसु कार्यक्रम होगा। इसमें वृहद झारखंड के अगुआ अजित प्रसाद महतो भी शामिल होंगे। अजित महतो ने कहा कि पुरुलिया से हजारों संस्कृति प्रेमी इस आयोजन में शामिल होंगे। टुसु झारखंड का एक महत्वपूर्ण लोक त्योहार है, जो फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। यह त्योहार झारखंड की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड की संस्कृति और कला को प्रदर्शित करना है, जो संस्कृति प्रेमियों को एक मंच प्रदान करना है। इस मौके पर दिलीप कडुआर, दाढ़ी वाला चन्दन, देबाशीष महतो, मंटू महतो, बिरसा महतो, केशव महतो, प्रह्लाद महतो, दीपक रंजीत आदि उपस्थित थे।

एसबीआई पेंशनर्स ने मनाई पिकनिक

JAMSHEDPUR : स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन,जमशेदपुर का पांचवां वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह बुधवार को दलमा हिल व्यू प्वाइंट, मेरीन ड्राइव, सोनारी में किया गया। इस पिकनिक में 97 सदस्यों ने सपरिवार प्राकृतिक वातावरण में पुनर्मिलन का आनंद लिया। समारोह की शुरूआत वरिष्ठ सदस्य आरएल भारद्वाज ने केक काट कर की। इसके बाद सहभोज कर कुछ आउटडोर खेल और अन्य गतिविधियों का आनंद उठाया। अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से सदस्यों के बीच वार्षिक कैलेंडर व उपहार वितरित किए गए।

बरही अंचल के चौकीदार पद की रिक्ति समाप्त

HAZARIBAG : उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में 6 दिसंबर को नियुक्ति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बरही अंचल अंतर्गत बीट संख्या-3/9, जिसमें 14 आवेदन स्वीकृत थे, किंतु 20 सितंबर को अनुकंपा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उस बीट के मृत चौकीदार के आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके आलोक में संबंधित बीट की रिक्ति समाप्त हो गई। 14 दिसंबर को उक्त बीट से संबंधित सभी 14 स्वीकृत अभ्यर्थियों का टंककीय भूलवश प्रवेशपत्र निर्गत हो गया है।

ओडिशा के कटक जिला में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं साहित्यकार

महेश्वर सोरेन को मिला संताली साहित्य अकादमी पुरस्कार

PHOTON NEWS JSR: ओडिशा स्थित मयूरभंज जिले के महेश्वर सोरेन को 2024 में संताली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। सोरेन की कविताएं और नाटक आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। उनके प्रमुख कार्यों में सिकरिया (कविता संग्रह), मने कोवाग धरम दाहर (नाटक) और सेचेड सावंता रेन अंधा मनमी (नाटक) शामिल हैं। महेश्वर सोरेन का जन्म 18 जनवरी 1980 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के जमुघीहा, पोस्ट- कुंदाबाई, थाना-उदाला में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम लालमोहन और बलही था। उन्होंने आरडीएस महाविद्यालय से बीएससी की। इसके बाद उन्होंने सरकारी आईटीआई, कटक से स्टेनोग्राफी की और एसआईपीएस झारपोखरिया से फामेर्सी में डिप्लोमा किया।

वह फार्मासिस्ट, नाटककार, कवि और संताली फिल्मों के कहानीकार हैं। कटक जिला के जगन्नाथपुर अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत महेश्वर सोरेन ने साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में संताली साहित्य पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनके लेख विभिन्न पत्रिकाओं, जैसे संधायनी, फागुन, टेटांग, जाहिरामगी, आदिम अरंग, सौनहेद अरंग, खोबोर कागज आदि में प्रकाशित हुए हैं। लेखन के साथ-साथ उन्होंने समाज में अच्छी प्रथाओं और मूल्यों को प्रस्तुत करने के लिए कई गांव स्तर की बैठकों का आयोजन भी किया है। एक नाटककार के रूप में उन्हें संताली साहित्य विकास समाज, शरत, बिरत आदिवासी होरिजाना सांस्कृतिक समारा, बालासोर, सरवना ट्रस्ट, भुवनेश्वर, बीएसटीएस सोनागाड़ी उदाला, मयूरभंज द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्हें ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से संताली साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो आदिवासी भाषा और संस्कृति अकादमी, ओडिशा द्वारा प्रदान किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने जुवान अनोलिया मान-2018 पुरस्कार ओडिशा शाखा से और पंडित रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार-2018 अखिल भारतीय संताली लेखक संघ से प्राप्त किया। वे एआईएसडब्ल्यूए, एआईएसएफडब्ल्यूए (जमशेदपुर), एएसईसीए उदाला शाखा के आजीवन सदस्य हैं। सिकरिया (कविता-2015) उनकी पहली पुस्तक है, मने कोवाग धरम दाहर (नाटक-2016) उनकी दूसरी प्रकाशित पुस्तक है और सेचेड सावंता रेन अंधा मनमी उनकी तीसरी प्रकाशित नाट्य पुस्तक है।

महेश्वर सोरेन

महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में पुरस्कार

बिहार के मैथिली साहित्यकार महेंद्र मलंगिया को उनके योगदान के लिए 2024 का मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। महेंद्र मलंगिया ने मैथिली साहित्य में नाटक, कविता और आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

शिक्षा मंत्री ने एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया बयान

CHAIBASA : राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने बुधवार को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराया। आचारसंहिता उल्लंघन मामले में अदालत ने दोनों को बयान कलमबंद किया है। दोनों पर विधानसभा चुनाव के दौरान सोनारी थाना में सिटी मैनेजर रविशंकर भारती द्वारा आचारसंहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में बताया गया था कि रामदास सोरेन और दिनेश कुमार अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगा रहे थे। गुप्त सूचना पर भारती वहां पहुंच गए और दोनों के खिलाफ सोनारी थाना में मामला दर्ज कराया था।

ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक से गिरकर शिक्षक की हुई मौत

ड्यूटी जाते समय एनएच-75 पर हुई दुर्घटना

AGENCY LATEHAR : जिला मुख्यालय के किन्नामाड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास बुधवार को एनएच 75 पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई। मृत शिक्षक की पहचान मेदिनीनगर निवासी संजय सिंह (42) के रूप में हुई है। मृत शिक्षक लातेहार के कुंदरी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित थे। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक संजय सिंह अपने घर से स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। रास्ते में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेने के बाद जैसे ही वह पेट्रोल पंप से बाहर रोड पर आए, इस दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी । घटना इतनी भीषण थी कि शिक्षक संजय सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल कर मृत शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक और स्थानीय लोग सदर अस्पताल पहुंच गए । शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की अनावश्यक बायोमेट्रिक सिस्टम है। शिक्षक संघ के नेता हीरा यादव और अजय कुमार ने बताया कि मात्र शिक्षकों के लिए वर्तमान में बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को सुबह स्कूल पहुंचकर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से अटेंडेंस बनाना है। इस कारण शिक्षक जल्दबाजी में स्कूल जाने को विवश होते हैं और इस प्रकार की घटना के शिकार होते हैं। शिक्षक संघ के नेताओं ने सरकार से मांग किया कि मृत शिक्षक के परिजनों को तत्काल 50 लाख रुपए मुआवजा और आश्रितों को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम पर भी रोक लगाने की मांग की गई ।

घटनास्थल पर जुटे लोग ● फोटोन न्यूज

झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल में 37 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग

JAMSHEDPUR : झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन बुधवार को भी फिल्मों की स्क्रीनिंग आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुई। विभिन्न भाषाओं एवं जॉनर की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 37 कैटेगरी में फिल्में दिखाई गईं। 8 म्यूजिक एलबम, 11 शॉर्ट फिल्म, 5 डॉक्यूमेंट्री , 4 फीचर फिल्म और 9 अंतराष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इसमें आयरलैंड, इटली, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देशों की फिल्में शामिल थीं। वहीं अलग-अलग राज्य से 6 भाषाओं पर जो हिंदी, नागपुरी, बंगाली, संथाली, अंग्रेजी, मुंडारी, कुरमाली, खोरठा भाषा की फिल्में प्रदर्शित की गईं। फिल्मों ने अपनी अनोखी कहानी, गहन भावनाओं और कलात्मक प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसमें राम द रियल हीरो, गोलगप्पा, हिड़ीज, ए काजल गे, बैड पैरेंटिंग, गुलमाल और जया जैसी कई अन्य फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य झारखंड की कला, संस्कृति और सिनेमा को बढ़ावा देना था।

2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, जागरूकता से ही जीतेंगे

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी ● फोटोन न्यूज

DHANBAD : राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम, धनबाद की ओर से बुधवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में टीबी जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि सरकार ने 2025 तक देश को टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सामूहिक भागीदारी से ही इस पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने छात्रों को टीबी के लक्षण, बचाव व इलाज के बारे में जानकारी दी। बताया कि टीबी किसी को भी हो सकता है, लेकिन सही इलाज से ठीक भी हो सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से टीबी मरीजों को दी जाने वाली निक्षय पोषण योजना आदि की जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. केके लाल, अधीक्षक डॉ. एसके चौरसिया, डीटीसी टीयू के वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक कौशलेंद्र कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक जावेद अंसारी, टीबीएचवी संजय कुमार जयसवाल, भारतीय रेडक्रास समिति के सलाहकार मधुरेंद्र कुमार सिंह आदि भी मौजूद थे।

पुलिस और आम जनता के बीच दूरी कम करना और विश्वास बढ़ाना जरूरी : एसपी

AGENCY KHUNTI : नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने तथा पुलिस और नागरिकों के बीच मौजूद अविश्वास और दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से खूंटी पुलिस के जरिये बुधवार को नगर भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार उपस्थित थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना और पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास का पुल तैयार करना है। कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया कि मामलों का निपटारा जल्द करायें। कुछ मामलों का मौके पर ही कर निष्पादन किया गया, जिन मामलों को तत्काल हल नहीं किया जा सका, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए दर्ज किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के जरिये कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और आवश्यक जानकारी आमजनों को दी गई। इनमें मुख्य रूप से गुमशुदा बच्चों और महिला सुरक्षा संबंधी कानून, पीड़ितों को मुआवजा, नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत जीरो एफआइआर एवं ऑनलाइन एफआइआर प्रणाली, डायल 112 तथा 1930 (साइबर फ्रॉड) एस.सी-एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम, संपत्ति मूलक अपराध, साइबर अपराधियों के जरिये ठगी के तरीके, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों का सेवन बिक्री की रोकथाम आदि के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई।

आम लोगों की शिकायत सुनते एसपी अमन कुमार ● फोटोन न्यूज

अल्पसंख्यकों को दी गई अधिकार व कर्तव्य की जानकारी

HAZARIBAG : विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर जिला कल्याण कार्यालय द्वारा बुधवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बताया कि ओबीसी, एसटी, एससी व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कल्याण विभाग में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जो विशेष कर इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए सहायक होती है। उन्होंने उपस्थित सभी नागरिकों को कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

हृदयाघात में छाती की पंपिंग कर बचाई जा सकती जान

PHOTON NEWS LATEHAR : समाहरणालय सभागार में बुधवार को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) पर कार्यशाला हुई, जिसमें उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता भी उपस्थित थे। इस दौरान डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सीपीआर हृदयगति रूक जाने के बाद जीवनरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक है। इसमें छाती पर पंपिंग करके या रोगी के मुंह में कोई व्यक्ति अपने मुंह से सांस भर कर बचा सकता है। यह एक मेडिकल थैरेपी की तरह है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। रिम्स के चिकित्सक डॉ. जसवंत ने सीपीआर तकनीक का डेमोस्ट्रेशन कर दिखाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीपीआर का पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटैशन है। इससे कार्डियक अरेस्ट और सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो कई बार किसी व्यक्ति की अचानक सांस रुक जाती है या कार्डिएक अरेस्ट की स्थिति में किसी को सांस नहीं आती है, तो सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। इसके साथ ही इससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई है तो पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगती हैं। वहीं, इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है, जिससे गंभीर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर सीपीआर दिया जाता है। इससे जान बचने की संभावना बढ़ जाती है।

सीपीआर का डेमो देते डॉ. जसवंत ● फोटोन न्यूज

सरकारी दस्तावेज में इस गांव का नाम है दर्ज, लेकिन आबादी शून्य

खूंटी जिले के बिरहोर चुआं गांव में नहीं रहता है कोई इंसान

AGENCY KHUNTI : गांव शब्द आते ही खपड़ैल मकान, पगडंडी, बच्चों की कोलाहल और मवेशी आदि से भरी किसी ऐसे स्थान की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जहां लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और पर्व-त्योहार मनाते हैं। वैसे गांव की परिभाषा ही है, जहां लोग एक साथ रहते हैं लेकिन सरकारी दस्तावेज में ऐसे कई गांव हैं, जहां कोई इंसान नहीं रहता। वहां के खेतों में दूसरे गांव के लोग खेती करते हैं। सरकारी भाषा में ऐसे गांव को बेचिरागी गांव कहते हैं। ऐसा गांव जहां चिराग जलाने वाला काई न हो। ऐसा ही एक बेचिरागी गांव है खूंटी जिले के रनिया प्रखंड का बिरहोर चुआं। सरकारी दस्तावेज में इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त है लेकिन आबादी शून्य है। यहां कोई घर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उस गांव में बिरहोर जनजाति के लोग रहते थे। बिरहारों को आमतौर पर घुमंतू माना जाता है, जो कुछ ही दिनों में अपना स्थान बदल देते हैं। दशकों पहले यहां आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोग रहते थे लेकिन धीरे-धीरे वहां के लोग गांव छोड़कर कहीं चले गये।

आसपास के गांव वाले बताते हैं कि बिरहोर एक चुंआ का उपयोग पानी पीने और अन्य कामों के लिए करते थे। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम बिरहोर चुंआ पड़ा। आज भी वह चुआं विद्यमान है। गांव के बिरहोर कहां गये और क्यों नहीं लौटे, इस संबंध में कोई कुछ नहीं बता पाता है। बिरहोर चुंआ गांव में एक आम के पेड़ के नीचे उनकी कब्रगाह आज भी मौजूद है। ग्रामीण बताते हैं कि कब्रगाह में मिट्टी के बर्तन में शवों के कंकाल हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के चिह्न उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण भी गांव के संबंध में कुछ नहीं बता पाते हैं। सरकारी अधिकारी सिर्फ इतना कहते हैं कि बिरहोर चुंआ नाम का गांव तो है लेकिन आबादी नहीं होने के कारण सभी जगह बेचिरागी के रूप में रिपोर्ट भेजी जाती है। गांव के नाम से कोई सरकारी योजना भी नहीं बनती है। जनगणना में भी जनसंख्या शून्य दशार्यी जाती जाता है। जयपूर के ग्राम प्रधान और सेवानिवृत्त शिक्षक एरियल संजय कंडुलना कहते हैं कि बिरहोर रस्सी और ओखली बनाकर बेचते थे। बंदर पकड़ा करते थे। माना जाता है कि उनका रोजगार नहीं चलने के कारण उन्होंने गांव छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बड़े-बुजूर्ग बताया करते थे कि बिरहोर समुदाय के लोग छपरी बनाकर रहते थे। वे कहां चले गये। इसकी किसी को जानकारी नहीं है। रनिया प्रखंड की प्रमुख नेली डहंगा ने कहा कि बिरहोर चुंआ दस्तावेजों में राजस्व गांव के रूप में दर्ज है। बिरहोर समुदाय के पलायन कर जाने के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है।

दो गांव हैं 'बेचिरागी'

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, खूंटी जिले में दो बेचिरागी गांव हैं। एक रनिया प्रखंड का बिरहोर चुंआ, जिसकी आबादी शून्य है। क्षेत्रफल 207.75 हेक्टेयर है। इसी प्रकार खूंटी प्रखंड के छोटा बांडी के नाम से एक ग्राम है, जहां कोई भी निवास नहीं करता है। छोटा बांडी का क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर है। रनिया प्रखंड में ही एक ऐसा गांव है, जिसमें सिर्फ एक ही परिवार निवास करता है। गांव का नाम चेंगरे है, जिसका कुल क्षेत्रफल 87 हेक्टेयर है। गांव में एक ही परिवार निवास करता है, जिसमें कुल नौ सदस्य हैं। इनमें पांच पुरुष और चार महिलाएं हैं।

बिचौलियों के पास धान न बेचें किसान : सुदीप गुड़िया

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विधायक सुदीप गुड़िया ● फोटोन न्यूज

KHUNTI : तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि किसान बिचौलियों के पास धान न बेचें। सरकार 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी कर रही है। विधायक बुधवार को तोरपा प्रखंड में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र के खुलने के साथ ही धान की खरीदारी शुरू हो गयी। विधायक सुदीप गुड़िया ने तोरपा प्रखंड के तपकारा, तोरपा तथा अम्मा लैंपस में भी धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उदेश्य है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। सरकार ने बोनस सहित 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि धान की खरीद में बिचौलिये हावी ना हों। किसानों को सीधा लाभ पहुंचे तथा समय पर भुगतान हो। मौके पर बीडीओ नवीन चंद्र झा, जिला परिषद सदस्य सुशांति कोनगाडी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रुबेन तोपनो, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के प्रखंड अध्यक्ष अमृत हेमरोम आदि उपस्थित थे।

BRIEF NEWS

विनोद बिहारी महतो की मनाई गई 33वीं पुण्यतिथि

RANCHI : झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से बुधवार को झारखंड आंदोलन के अमर पुरोधा स्व। विनोद बिहारी महतो की 33वीं पुण्यतिथि पर डोरंडा स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गयी। आंदोलनकारियों ने ह्विनोद बिहारी महतो अमर रहेह्व के नारे के साथ स्व। महतो को श्रद्धांजलि दी और उनके अरमानों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि विनोद बिहारी महतो अखंड झारखंड के पक्षधर थे। वे हमेशा राज्य के लोगों को ह्लपढ़ो और लड़ोह्व का नारा देते हुए उन्हें एकजुट करते थे और अपने हक अधिकार के लिए प्रेरित करते थे।

2444 लोगों की शिकायतों का हुआ निपटारा

RANCHI : झारखंड पुलिस के बैनर तले रांची छोड़कर राज्य के सभी जिलों में आज (18 दिसंबर) जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 2444 आम लोगों की समस्याएं पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुनी गई और उसका समाधान किया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरूआत हुई है। जानकारी के अनुसार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी गई और उनकी मदद की गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में 23 आईजी, डीआईजी और कमांडेंट रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया था। प्रतिनियुक्त अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देश का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं, आम जनता से मिली शिकायत का सही तरीके से निवारण किया जा रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे।

प्राथमिक व मवि के छात्रों का 'अपार' कार्ड बनाना अनिवार्य

RANCHI : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजीलॉकर में अपलोड हो जाएगा, और छात्र का डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण उनका आधार कार्ड बनाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति के कारण गरीब छात्रों के लिए अपार आईडी कार्ड बनवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

थानेदार पर कुख्यात अपराधी सजाउद्दीन के गिरोह को संरक्षण देने का आरोप

पिठोरिया में रंगदारी के लिए युवक पर किया जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के पिठोरिया थाना के थानेदार गौतम कुमार रॉय पर लगातार कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। इससे पिठोरिया इलाके के कुख्यातों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कुख्यात अपराधी सजाउद्दीन और उसके गुर्गों ने रंगदारी के लिए कोकदोरो निवासी सफदर सुल्तान पर जानलेवा हमला किया। इससे सफदर सुलतान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। थानेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना से पहले से ही पिठोरिया थानेदार पर लगातार संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। चूंकि कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी थानेदार सजाउद्दीन और उसके गुर्गों को गिरफ्तार करने के बजाय राहत दे रहे हैं, जबकि सजाउद्दीन जिला बदर अपराधी रह चुका है। कई मामलों में वारंटी भी है।

कई एफआईआर होने के बाद भी थाना प्रभारी नहीं कर रहे कार्रवाई, थानेदार को हटाने की मांग

अपराधियों का बढ़ा मनोबल, लगातार दे रहे घटनाओं को अंजाम | पीड़ित का आरोप- मोटी रकम लेकर अपराधियों को छोड़ रहे थानेदार

"घटना की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जहां तक थानेदार पर संरक्षण के जो आरोप हैं, इसकी जांच की जा रही है। पुष्टि होने पर थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
-सुमित अग्रवाल, एसपी, ग्रामीण।

20 लाख मांगी रंगदारी, फिर किया जानलेवा हमला

जानलेवा हमला करने की घटना को लेकर सफदर सुल्तान ने कोकदोरो निवासी सजाउद्दीन अंसारी, शाहिद अंसारी उर्फ छोटू उर्फ तारीफ अंसारी, रमीज अंसारी, इरशाद अंसारी, खालिक अंसारी, बबलू उर्फ अर्सलान अंसारी, समशाद अंसारी, शहबाज अंसारी, और उपरकोनकी निवासी साहिल अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि बुधवार की सुबह करीब 9 बजे एक जमीन पर उनकु झाड़ियों की साफ-सफाई करवा रहे थे। इस दौरान वहां बलेनो कार **(JH01-FB-3929)** में सवार होकर सभी अपराधी पहुंचे और 20 लाख की रंगदारी की मांग की और जान मारने की धमकी दी। इसके बाद चारदीवारी को लात से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद करीब 11:55 बजे संबंधित जमीन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित वे अपने निर्माणाधीन मकान और मार्केट में अपने छोटे बच्चे के साथ खड़े होकर निर्माण कार्य देख रहे थे। उसी दौरान वहां महिंद्रा थार **(JH01-FF-1471)** और बलेनो कार **(JH01-FB-3929)** में सवार होकर पहुंचे और जान मारने की नीयत से हमला कर दिया।

गिरफ्तारी नहीं होने से बढ़ता जा रहा मनोबल

पुलिस द्वारा सजाउद्दीन को हिरासत में लेकर छोड़ देने के बाद इसका मनोबल और भी बढ़ गया है। रंगदारी, जमीन पर कब्जा, मारपीट जैसे घटनाओं को अब ये लगातार अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में भी सजाउद्दीन व इसके गिरोह के खिलाफ कई लोगों ने अलग-अलग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन, पुलिस ने अब तक कोई कारवाई नहीं की है।

संरक्षण की वजह से पनपा सजाउद्दीन

पीड़ित परिवार का कहना है कि थानेदार गौतम कुमार रॉय का अपराधियों से गठजोड़ है। थानेदार के संरक्षण से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। हर काले धंधे में थानेदार का कमीशन तय है। यही कारण है कि जिला बदर कुख्यात सजाउद्दीन व अन्य मनचलों का मनोबल बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में सजाउद्दीन और इसके गुर्गे द्वारा मारपीट, रंगदारी, जान मारने की धमकी, पिस्टल दिखाकर लूटपाट, जान मारने की नीयत से हमला व अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर रांची के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद पुलिस अब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी।

कोर्ट के बाहर से पकड़ाया, पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया

पीड़ित परिवार के अनुसार, 12 दिसंबर को कुख्यात सजाउद्दीन अपने गुर्गों के साथ कोर्ट पहुंचा था। दरअसल, सजाउद्दीन पर दर्ज कई मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। कांके थाना में दर्ज केस नंबर 328/2024 में सजाउद्दीन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। इसी केस में जमानत पाने के लिए सजाउद्दीन अपने गुर्गों के साथ पहुंचा था। उसे कोर्ट के बाहर हिरासत में भी लिया गया। लेकिन, कुछ देर के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

आश्वासन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

पिछले महीने नवंबर में सजाउद्दीन व इसके गुर्गों ने रांची के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया था। इस दौरान थाना प्रभारी ने सजाउद्दीन व उसके गुर्गों को दो दिनों के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस लौटे थे। लेकिन, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

28 सितंबर को आधिकारिक रूप से गिरिडीह पुलिस के समक्ष किया था सरेंडर

54 कांडों में शामिल कुख्यात नक्सली रामदयाल से राज उगलवा रही एनआईए

- लिया गया है चार दिनों की रिमांड पर, तोपचांची थाना उड़ाने का भी है आरोपी

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। बचे नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है- झारखंड से जल्द ही माओवादियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के साथ साथ सीबीआई और एनआईए भी कई मामलों को टेकओवर करते हुए जांच कर रही है। इसी क्रम में एनआईए ने 54 नक्सली वारदातों में शामिल रहे कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन को चार दिनों की रिमांड पर लिया है। महतो से सघन पूछताछ चल रही है। नक्सलियों के कई गुप्त राज की एनआईए महतो से उगलवा रही है। रामदयाल महतो तोपचांची थाना को उड़ाने का भी आरोपी है। रामदयाल महतो ने इस साल 28 सितंबर को आधिकारिक रूप से गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पीरटांड़ थाना क्षेत्र के पीपराडीह निवासी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन धनबाद के तोपचांची थाना उड़ाने एवं एसएलआर सहित लगभग 07-08 हथियार को लूटने के मामले में अहम भूमिकी निभाई थी। इसके अलावा साल 2022 में रामदयाल की अगुवाई में ही डुमरी थाना के तेलियाबहियार गांव में उप मुखिया असलम अंसारी को पुलिस मुखबिर घोषित कर गोली मारकर हत्या की गई थी। रामदयाल के विरुद्ध झारखंड में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। गिरिडीह व धनबाद जिले के 54 नक्सली वारदातों में वह शामिल रहा है। गिरिडीह जिले के 43 कांड एवं धनबाद जिले के 11 कांडों में पुलिस को रामदयाल की तलाश थी।

मानव अधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष बने वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला

RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला को बुधवार को वर्ष 2024-26 के लिए मानव अधिकार मिशन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही दीपक कुमार को प्रदेश महासचिव, मनोज कुमार, सोहनी राय, डॉ एके सिन्हा एवं सुरेश गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के कुल 28 पदाधिकारियों का भी मनोनयन किया गया है। मानव अधिकार मिशन संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) से एफिलिएटेड है। साथ ही नीति आयोग के अंतर्गत निर्बंधित है। इस संस्था के मुख्य संरक्षक देश के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बालाकृष्णन हैं। संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और केंद्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा डॉ ममता शर्मा हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ महेंद्र शर्मा हैं।

कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च, मणिपुर और अडानी मामले में उठाए सवाल

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अडानी व उनके सहयोगियों को बचाने और साथ ही मणिपुर में जारी हिंसा की अनदेखी करने के विरोध में एक विशाल राजभवन मार्च का आयोजन किया। यह मार्च प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में शहीद स्थल से राजभवन तक निकाला गया। मार्च बाद में एक सभा में तब्दील हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी और मणिपुर मामले पर पूरी तरह मौन है। उन्होंने कहा मणिपुर में हिंसा जारी है और कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन, प्रधानमंत्री ने अब तक वहां का दौरा नहीं किया। मणिपुर को लेकर मोदी जी की चुप्पी और अडानी के मामले पर सरकार की अनदेखी चिंताजनक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मणिपुर मामले पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह झारखंड में कई बार आए, लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा पर उनके पास समय नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी मामले में मोदी सरकार भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने कहा कि मोदी जी संविधान से मिली ताकत को भूल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अडानी को बचाने की कोशिश की गई तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा द्वारा संविधान और बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है।

राजभवन मार्च करते कांग्रेस नेता। ● फोटोन न्यूज

झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए डीजीपी व एटीएस एसपी

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों की सही तरीके से सैंपलिंग नहीं करने, जिससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपितों को जमानत मिलने और एनडीपीएस केस में आरोपितों की सजा की दर कम होने के मामले में बुधवार को राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्ट अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाएं ताकि पुलिस की ओर से जब्त किये गये मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो। इसके साथ मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़े केस में सजा की दर बढ़े और मादक पदार्थ के कारोबारियों को सख्त सजा मिले।

दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात मिलने पहुंचीं मंत्री दीपिका पांडे

RANCHI : ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बेटी से गुजरात के वड़ोदरा में मुलाकात की। साथ ही उसका हाल जाना। मंत्री के साथ गई टीम ने ना सिर्फ बच्ची का हाल जाना, बल्कि उसे आर्थिक मदद पहुंचाते हुए पीड़िता के परिजन को चार लाख रुपये का चेक भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ आईजी सुमन गुप्ता भी थे।

केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार आरोप लगा रही है झामुमो : बाबूलाल

PHOTON NEWS RANCHI : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि झामुमो के जरिये हवा-हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि यदि झामुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है, तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने

रखें। झामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि ये राशि किस मद की है? कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। मरांडी ने कहा है कि महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये, किसानों को प्रति क्विंटल धान के 3,200 रुपये और युवाओं को नौकरी देने के झूठे वादे का भंडाफोड़ हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर आप अपनी विफलताओं को छिपा सकते।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा कराने वाली एजेंसी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

RANCHI : हाईकोर्ट से 28 जनवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सचिवालय सहायक (सीजीएल) परीक्षा आयोजित कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जेएसएससी की ओर से एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किये जाने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। सिंगल बेंच ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश को सही ठहराया था। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने बहस की।

तकलीफ : रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान में 205 परिवारों के उजड़ गए घर

कड़ाके की ठंड में तोड़ दिया गरीबों का आशियाना

PHOTON NEWS RANCHI : रांची रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते रांची के बिरसा चौक पर रहने वाले 205 परिवारों के घर उजड़ गए हैं। नतीजतन, सभी को टेंट और आग के सहारे ये सर्द रातें गुजारनी पड़ रही हैं। जब तक अलाव जलता है, तब तक नींद आती है, लेकिन जैसे ही अलाव बुझता है, नींद फिर टूट जाती है और फिर ठंड के कारण नींद नहीं आती। अपना दर्द बयां कर रही दुलारी देवी पिछले 44 वर्षों से वहां मकान बनाकर रह रही थीं, लेकिन चूंकि जमीन रेलवे की थी, इसलिए रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुलारी देवी जैसे 204 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, वे

बताते हैं कि वे इस जमीन पर तब रहने आए थे, जब यहां जंगल हुआ करता था। उस समय किसी को पता नहीं था कि यह जमीन रेलवे की है। तब से उन्होंने यहां अपनी झुग्गी-झोपड़ी डाल ली और रहने लगे। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनमें से कई लोग अपने शहर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ को उम्मीद है कि सरकार की ओर से उन्हें कुछ मदद मिलेगी। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्होंने सरकार पर भी उंगली उठाई है। उनका कहना है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अधिकांश परिवारों ने अबुवा आवास के लिए आवेदन किया था। चुनाव से पहले उनसे कहा गया था कि सभी को जल्द से जल्द अबुवा आवास मिल जाएगा।

44 सालों से रह रहे थे कई परिवार

हाड़ कंपा देने वाली ठंड में रेलवे द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण 204 परिवारों के मकान उजड़ गए हैं और अब वे सड़क पर आ गए हैं। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, वे बताते हैं कि वे बिरसा चौक के पास अपनी झुग्गी-झोपड़ी बनाकर पिछले 44 वर्षों से रह रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे कहां जाएं और क्या करें। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बिरसा चौक के पास जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। वे प्रतिदिन मेहनत करके अपना घर चलाते थे। इसी मेहनत के बल पर उन्होंने कुछ ईंट जोड़कर एक अस्थायी छत बनाई थी। जिसमें उनके सपने साकार हो रहे थे और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है।

किराए का घर लेने का भी नहीं दिया गया मौका

65 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुसुम देवी ने बताया कि वे पिछले 45 वर्षों से इस जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही थीं। लेकिन अचानक सब कुछ तबाह हो गया, इतना भी समय नहीं दिया गया कि वे किराए का मकान ले सकें। एक तरफ सरकार गरीबों को बसा रही है, वहीं जिला प्रशासन उन्हें बेदखल करने में लगा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दिनेश का घर भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। दिनेश का कहना है कि वह पुरुष हैं और बाहर रह सकते हैं, लेकिन महिलाएं इस स्थिति में कैसे रहेंगी, यह बहुत मुश्किल सवाल है। दिनेश के मुताबिक पहले रेलवे प्रशासन ने कहा था कि वे 15 दिन का समय देंगे, लेकिन अचानक बुलडोजर आया और उनके घरों को ढहाकर चला गया।

राज्यपाल ने एनआईएमटी में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन

RANCHI : बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएमटी) के डिपार्मेंट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज और द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर (इंडिया), झारखंड के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। एनआईएमटी के सम्मेलन का विषय एडवांस इन फाउंड्री एंड फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी था। सम्मेलन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति और सतत विकास में योगदान देना है। राज्यपाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि फाउंड्री और फॉर्मिंग तकनीक औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तकनीकों का उपयोग निर्माण, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।

स्कूल के समय पुलिस गश्त की व्यवस्था करने की उठी आवाज

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राजधानी रांची में छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से विधि व्यवस्था में सुधार की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि रांची सहित पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और स्कूल- कॉलेजों के समय पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए, ताकि छात्र-छात्राएं सुरक्षित रह सकें। अजय राय ने कहा कि वर्तमान में छेड़खानी और हत्याओं की घटनाओं से अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार से विधि व्यवस्था के मामलों में गंभीरता दिखाने की अपील की, ताकि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। राय ने यह भी सुझाव दिया कि

राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कड़े कदम उठाने और छेड़खानी के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और छात्र-छात्राएं अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। अजय राय ने यह भी कहा कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।

समाचार सार

युवा महोत्सव में चक्रधरपुर की सौरभी दत्ता प्रथम

CHAKRADHARPUR : मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर की छात्रा सौरभी दत्ता ने अपनी अद्भुत कलात्मक प्रतिभा से क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

सौरभी ने प्रमंडल स्तरीय युवा महोत्सव-2024 की चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले सौरभी ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव में भी पहला स्थान हासिल किया था। कॉलेज के निदेशक श्याम लाल महतो ने कहा सौरभी की यह उपलब्धि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इस जीत से कॉलेज और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।

केंद्रीय विद्यालय में चला नेशनल जेंडर कैंपेन

CHAKRADHARPUR : शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में नेशनल जेंडर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर ने स्त्री रोग विशेषज्ञ व समाजसेवी डॉ. रीना गोडसोरा मुर्मू को आमंत्रित किया था। उन्होंने कक्षा 9 से 12 के बच्चों को लिंग आधारित हिंसा, उसके विभिन्न प्रकार हानिकारक परिणाम की जानकारी दी। डॉ. रीना गोडसोरा मुर्मू ने बताया कि अतुल सुभाष केस इसका हालिया उदाहरण है, यह हिंसा पुरुष या महिला किसी के साथ भी हो सकती है। बच्चों ने इससे संबंधित कई सवाल पूछे और अपनी शंका दूर की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल विश्वनाथ हांसदा सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

अनियमित विद्युत आपूर्ति से ग्रामीण परेशान

GHATSILA : प्रखंड के बीहड़ गांव बासाडेरा के ग्रामीण अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान हैं। ट्रांसफर्मर में आई खराबी के कारण ग्रामीण एक सप्ताह से अंधेरे में थे। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू को बिजली की समस्या से अवगत कराया। मुर्मू विभागीय मिस्त्री को लेकर कालचित्ति पंचायत अंतर्गत बासाडेरा गांव बुधवार को पहुंचीं तथा ट्रांसफॉर्मर में आई खराबी को ठीक कराई। इसके बाद गांव में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। ग्रामीणों ने देवयानी मुर्मू को बताया कि महीने में चार पांच बार बिजली लाइन में खराबी आ जाती है। इस कारण अंधेरे में रहना पड़ता है। कभी कभी शाम के समय बिजली काट दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो जाती है। मुर्मू ने विभागीय पदाधिकारियों से बात कर समाधान निकालने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया।

रिपब्लिक डे कैंप के लिए श्रुति रॉय का चयन

GHATSILA : संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर की छात्रा श्रुति रॉय प्री-रिपब्लिक डे कैंप-4 सह रिपब्लिक डे 2025 लॉन्चिंग कैंप के लिए बुधवार को राजेंद्रनगर पटना रवाना हुई। यह कैंप 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक होगा। इस कैंप में चयन से पहले श्रुति रॉय ने कुल 6 अलग-अलग कैंप में बेहतर प्रदर्शन किया था। इस कैंप के पश्चात श्रुति रॉय दिल्ली में होने वाले रिपब्लिक डे कैंप-2025 के लिए रवाना होगी। विद्यालय प्रबंधक सह एनसीसी अधिकारी डॉ. प्रसेनजीत कर्मकार, प्राचार्या नीलकमल सिन्हा, समस्त विद्यालय परिवार तथा सभी एनसीसी कैडेट्स ने श्रुति को उसके यात्रा और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामना दी। अपनी श्रेणी में श्रुति रॉय पूर्वी सिंहभूम जिले से एकमात्र प्रतिभागी होगी।

एमसीसी चाईबासा ने यंग झारखंड को हराया

CHAIBASA : चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे ग्रुप लीग मुकाबले में बुधवार को मिडिलसेक्स क्रिकेट क्लब चाईबासा ने गत वर्ष की चैंपियन टीम यंग झारखंड क्रिकेट क्लब चाईबासा को 48 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही एमसीसी के चार मैच में कुल छह अंक हो गए हैं और अंक तालिका में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कल ग्रुप लीग मुकाबले में एमसीसी चाईबासा का मुकाबला गत वर्ष की उपविजेता टीम सेरसा चक्रधरपुर से निर्धारित है।

टेल्को में होगा जैम एट स्ट्रीट

JAMSHEDPUR : टेल्को में 22 जनवरी को जैम एट स्ट्रीट का आयोजन होगा। टाटा स्टील यूआईएसएल ने बताया कि रविवार को सुबह 6.30 बजे से टेल्को लेबर ब्यूरो गोलचक्कर से डीलर्स हॉस्टल तक होने वाले इस कार्यक्रम में पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, योगा, बैंडमिंटन, जुम्बा समेत कई तरह के हुनर का प्रदर्शन कलाकार करेंगे। ज्ञात हो कि माह के अंतिम रविवार को टाटा स्टील द्वारा यह आयोजन किया जाता है।

कदमा में दिनदहाड़े अपराधियों ने की फायरिंग, सीने में मारी चार गोलियां

सुबह-सुबह घर से निकलते ही घात लगाए बदमाशों ने किया हमला

PHOTON NEWS JSR : कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में बुधवार सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना को सीने में चार गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि, आलोक के साथियों ने उसे इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिचितों ने बताया कि आलोक अपनी बुलेट पर सुबह घर से निकला था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दी।

बन्ना गुप्ता का समर्थक था आलोक : मृतक आलोक पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का समर्थक था। चुनाव के दौरान भी उसने बन्ना गुप्ता के लिए प्रचार किया था। वह कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान रखता था।

आलोक भगत की फाइल फोटो

काली पूजा विसर्जन के दौरान हुआ था विवाद

चार नवंबर को काली पूजा विसर्जन के दौरान मारपीट हुई थी। इस दौरान आलोक के भाई मनोज भगत के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। मनोज भगत ने शिकायत में बताया था कि काली पूजा विसर्जन के दौरान छोटू बच्चा, आकाश सिंह, नरेश सिंह समेत 10-15 लोगों ने घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। छोटू बच्चा ने भाई पर हथियार तान दिया था। यह मारपीट बीच-बचाव में हुई थी।

25 दिन पूर्व ही हुई थी आलोक की शादी

बता दें कि 25 दिन पूर्व ही 24 नवंबर को आलोक की शादी हुई थी। शादी के एक माह भी नहीं बीते थे कि उसकी हत्या कर दी गई। इधर, घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

राजनीतिक हत्या, त्वरित कार्रवाई हो : बन्ना गुप्ता

राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह राजनीतिक हत्या है। चुनाव के दौरान गला फाड़ कर भय और अपराध मुक्त जमशेदपुर बनाने का झूठा प्रचार करने वाले विधायक और झूठ के सौदागर सरयू राय द्वारा पोषित अपराधियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक भगत ऊर्फ मुन्ना की दिनदहाड़े हत्या की है। इस संबंध में यदि त्वरित कार्यवाई नहीं हुई और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो डीजीपी और मुख्यमंत्री से मिलूंगा, यह एक राजनीतिक हत्या है। कई कांग्रेस के साथियों को भी धमकी मिल रही हैं, यदि पुलिस किसी के दवाब में कार्य करती हैं तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा।

आपस में ही भिड़ रहे आपराधिक गिरोह : सरयू

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि बन्ना गुप्ता के संरक्षण में चल रहे आपराधिक गिरोह अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। शास्त्रीनगर के आलोक भगत की हत्या बन्ना समर्थित आपराधिक गिरोहों की परपस्पर प्रतिद्वंद्विता का ही परिणाम है। सत्ता का दबाव हटते ही बन्ना गुप्ता के संरक्षण में चल रहे गिरोह आपस में ही भिड़ने लगे हैं। राय ने कहा कि जिन लोगों को हथियार बना कर बन्ना गुप्ता ने पिछले पांच वर्षों में जमशेदपुर में भय और आतंक का साम्राज्य खड़ा किया था, वे अब खुद भयभीत और आतंकित हैं। उनका यह भय और आतंक कहीं बाहर से नहीं, बल्कि एक ही थैली के चट्टे-बट्टों का आपसी संघर्ष है। पुलिस इसकी छानबीन करे और बन्ना गुप्ता द्वारा पिछले पांच वर्षों में कायम किए गए भय और आतंक के माहौल का पदार्फाश करे।

एचसीएल के माइनिंग फोरमैन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत

GHATSILA : मुसाबनी थाना क्षेत्र के माइनिंग फोरमैन प्रवीण सी. रेवती की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सुरदा क्रॉसिंग स्थित जाहेरथान के समीप ड्यूटी जा रहे रेवती की बाइक को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। यह दुर्घटना मुसाबनी-घाटशिला मुख्य सड़क पर बुधवार को हुई। हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर के चिथड़े हो गए। हालांकि सुरदा क्रॉसिंग के पास बैठे झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन दौड़कर अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, परंतु तब तक प्रवीण की मौत हो चुकी थी। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के डीजीएम दीपक कुमार श्रीवास्तव, माइंस मैनेजर डीजे सोम, एचआर हेड अर्जुन लोहरा, विनय कुमार, डीजीएम श्रवण कुमार झा मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रवीण मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले थे। यहां जीनियस कंसल्टेंट के जरिए 1 साल के कांट्रैक्ट पर सुरदा माइंस में आए थे।

रांगड़ा में 8 हजार लीटर नकली विदेशी शराब जब्त

जब्त शराब के साथ मौजूद पुलिसकर्मी ● फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ आरपीएफ क्षेत्र के रांगड़ा रेलवे साइडिंग में बढ़ते कोयला तस्करी के बीच अब अवैध शराब का कारोबार भी सामने आने लगा है। इस बात का पता तब चला, जब बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने रेल साइडिंग से सटी बस्ती में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो नजारा सामने आया, उसे देखकर आबकारी विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। टीम ने वहां 8 हजार लीटर नकली विदेशी शराब और 290 लीटर देसी शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार रांगड़ा रेलवे साइडिंग के 12 नंबर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बसी बस्ती में पिछले कुछ दिनो से अवैध कारोबार चल रहा है। आरपीएफ और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से रांगड़ा रेलवे साइडिंग की इस बस्ती में पहले कोयला और अब नकली शराब का उत्पादन होने लगा है।

एसडीओ ने जब्त किया 1200 सीएफटी बालू

CHAKRADHARPUR : एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी के नेतृत्व में बुधवार को चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के बंगलाटांड़ और उलीडीह में छापेमारी कर लगभग 1200 सीएफटी बालू जब्त किया गया। यह अवैध भंडारण दो जगहों पर किया गया था। इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि अवैध रूप से बालू का भंडारण कर बेचा जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना मिली थी। एसडीओ ने जेसीबी मशीन बुलाकर ट्रैक्टर और डंपर से सभी बालू को जब्त कर चक्रधरपुर थाना लाया गया। बता दें कि मंगलवार को डीसी ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में रूप से अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिया था। छापेमारी में एसडीओ के अलावा चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन, पोड़ाहाट डीएसपी कपिल चौधरी सहित बड़ी संख्या मे पुलिस बल थे।

जगन्नाथपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म व उसकी मौत से बवाल

स्थानीय लोगों ने आरोपी की कर दी जमकर पिटाई, पुलिस को सौंपा

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में मंगलवार शाम को एक किशोरी छात्रा की दुष्कर्म के बाद मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 7 बजे नाबालिग छात्रा घर के पीछे आंगनबाड़ी केंद्र के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। उसका शरीर अस्त-व्यस्त देख परिजनों के होश उड़ गए। उसे आनन-फानन जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए चम्पुआ रेफर कर दिया गया। चम्पुआ में इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर चंपुआ में भी आग की तरह फैली तो वहां के लोग भी आक्रोशित हो गए। सैकड़ों लोग चम्पुआ अस्पताल पहुंच गए। सभी आरोपी को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने माहौल को किसी तरह शांत कराया। वहीं नाबालिग की मौत की खबर से जगन्नाथपुर में भी लोग उग्र हो गए। लोगों ने पास की बस्ती रहीमाबाद में रहने वाले आरोपी युवक मो. अजमल को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. बिगड़ते माहौल को देख हाटगम्हरिया, जेटिया व नोवामुंडी थाना की पुलिस समेत जगन्नाथपुर एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे। लोगों को शांत कराया। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तारी कर लिया गया है। पुलिस मामले पर और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर घटना के बाद पुलिस ने मृतक नाबालिग का शव अपने कब्जे में लेकर बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही पोस्टमार्टम हाउस में भी भारी भीड़ जमा हो गई।

पोस्टमार्टम हाउस के पास लगी भीड़

डीआईजी-एसपी ने सुनी जनता की फरियाद

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी थाना क्षेत्र की जनता की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बुधवार को पिल्लई हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हुआ, जिसमें डीआईजी, कोल्हान मनोज रतन चौथे व एसपी आशुतोष शेखर भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में डीआईजी व एसपी ने जनता की फरियाद सुनी। कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया, जबकि कुछ को अधीनस्थ पदाधिकारियों को अग्रसारित कर दिया गया। उन्हें जांच के उपरांत यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए गया।

बागजाता माइंस के मजदूरों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी

माइंस के गेट पर धरना देते मजदूर ● फोटोन न्यूज

GHATSILA : बागजाता माइंस रेंज समूह के मजदूरों को काम देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। इसके कारण माइंस में एक भी मजदूर नहीं जा सके। मजदूरों का कहना है कि 9 माह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति चिंताजनक हो गई है। बुधवार को यूसिल प्रबंधक द्वारा आंदोलनकारी मजदूरों से बात कर आवश्यक सेवा बहाल करने के लिए अनुमति मांगी गई। इसके बाद मजदूरों ने आवश्यक सेवा बहाल करने के लिए इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले मजदूरों को बागजाता माइंस तक जाने की अनुमति दी और बागजाता माइंस में आवश्यक सेवा चालू हो गई। आंदोलनकारी मजदूरों से मिलने जाम स्थल पर जिप प्रतिनिधि सह पूर्व जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू पहुंचे और आंदोलन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मजदूरों के आंदोलन को समर्थन की घोषणा करते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति की मौत

GHATSILA : अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में इलाजरत एक अज्ञात व्यक्ति की बुधवार को मौत हो गई। गालूडीह थाना के एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व गालूडीह रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे यह व्यक्ति पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना के बाद उसे अनुमंडल अस्पताल लाया गया था। उसके पास कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। अनुमंडल अस्पताल घाटशिला के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएन सोरेन ने बताया कि ब्लड प्रेशर अधिक होने के करण उसकी मौत हुई। अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। मौत के बाद घाटशिला के समाजसेवी कलीराम शर्मा ने निजी खर्चे से पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर भेजा।

गोइलकेरा में विधायक ने किया धान खरीद केंद्र का उद्घाटन

धान खरीद केंद्र का उद्घाटन करते विधायक जगत माझी ● फोटोन न्यूज

GOILKERA : गोइलकेरा बाजार स्थित लैम्पस कार्यालय में मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने बुधवार को धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक की उपस्थिति में ही धान क्रय की शुरूआत हुई। विधायक ने कहा कि केंद्र का उद्घाटन होने से यहां सरकारी दर पर धान बेचने में किसानों को सुविधा होगी। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखें। उन्होंने किसानों से केंद्र में ही धान बेचने की अपील की। बता दें कि गोइलकेरा प्रखंड के आराहासा, बारा, बिला, गम्हरिया, केदा, केबरा, कुईड़ा, तरकटकोचा व कदमडीहा पंचायत के किसान यहां धान बेच सकेंगे। किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी। गोइलकेरा प्रखंड में 15 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यहां कुल 158 पंजीकृत किसान हैं।

कार्य में शिथिलता बरतने के लिए कार्यपालक अभियंता एनआरईपी व भवन प्रमंडल को किया गया शोकॉज

घाटशिला में मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश

PHOTON NEWS JSR : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें अनाबद्ध निधि, सीएसआर, एमपी-एमएलए फंड, डीएमएफटी, पर्यटन एवं कला संस्कृति, खेलकूद विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में कार्यप्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने बुरूडीह डैम में तकनीकी खामियों के कारण नौका विहार नहीं होने पर अप्रसन्नता जताते हुए एसडीओ, कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल, जिला खेल पदाधिकारी को कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर समस्या को हल करने का निर्देश दिया। वहीं घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश जिला खेल पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्वीकृत सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर कार्यपालक अभियंता एनआरईपी एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया। बैठक में निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, संबंधित तकनीकी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते उपायुक्त अनन्य मित्तल ● फोटोन न्यूज

लापरवाही बरतने पर संवेदक को करें ब्लैकलिस्टेड

समीक्षा में जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल स्वीकृत 24 योजनाओं में 22 पूर्ण एवं 2 अपूर्ण, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल 80 योजनाओं में 68 पूर्ण एवं 12 अपूर्ण तथा 2024-25 के कुल 38 योजनाओं में 35 पूर्ण 3 अपूर्ण पाए गए। उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाते हुए जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही की जा रही हो तो नोटिस देते हुए एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई करें, भूमि संबंधी समस्या होने पर सीओ से समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण कराएं।

एमपी-एमएलए फंड को दें प्राथमिकता

सीएसआर फंड की समीक्षा में सिविल सर्जन को 15 जनवरी तक आवंटित राशि के व्यय का निर्देश दिया गया। इस मद से यूसीआईएल खनन क्षेत्र अंतर्गत जनमानस की स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक भवन, हाईमास्ट लाइट, पथ का सदृढ़ीकरण आदि कार्य किया जा रहा है। कुल 11 योजनाओं में 5 पूर्ण कर लिए गए हैं। एमपी-एमएलए फंड की स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सांसद व विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य पूर्ण कराएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 8 फुटबॉल स्टेडियम

पर्यटन एवं कला संस्कृति, खेलकूद विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं कुल 16 योजनाओं में 8 फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जानी है। चाकुलिया (माइदाबांध) एवं जमशेदपुर (सरजामदा) की एक-एक योजना में 50 फीसदी से ज्यादा कार्य हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। वहीं पटमदा, धालभूमगढ़, गुड़ाबांदा, बहरागोड़ा, पोटका एवं जमशेदपुर के घाघीडीह पंचायत एवं करनडीह की योजना में एक योजना एकरारनामा की प्रक्रिया में है, तीन का कार्य प्रारंभ एवं एक योजना में पुनरीक्षित प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया गया है। लंबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अन्य योजनाओं में सौंदर्यीकरण कार्य, स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन, नौका विहार सामग्री आपूर्ति के कार्य शामिल हैं।

बुरुडीह डैम में बोटिंग शुरू करने के लिए ग्राम सभा ने दिया अल्टीमेटम

एसडीओ को ज्ञापन देते ग्राम सभा के पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

GHATSILA : संयुक्त ग्राम सभा द्वारा 15 दिसंबर को बुरुडीह गांव में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 4 अक्टूबर को अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला के समक्ष मांग की गइ थी कि नौका परिचालन संयुक्त ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। इसके बावजूद संयुक्त ग्राम सभा को बोटिंग की जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। बुधवार को संयुक्त ग्राम सभा के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र को मांग पत्र सौपा, जिसमें अनुमंडल प्रशासन से मांग की गई है कि एक सप्ताह के अंदर नौका परिचालन की जिम्मेदारी संयुक्त ग्राम सभा को नहीं दी गई, तो बाध्य होकर ग्राम सभा अपनी ओर से बोटिंग शुरू कर देगी। पर्यटकों को ग्रामसभा निराश होकर लौटने नहीं देगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सीमांतो बारिक, नारायण नायक, नंदो हांसदा, जोसेफ मुर्मू आदि शामिल थे।

जांच में 8 वाहन जब्त, 10 पर लगाया 57 हजार जुर्माना

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर साकची, बिष्टुपुर और जुगसलाई में बुधवार को ऑटो व बस के कागजातों की जांच की गई। मोटर यान निरीक्षक सूरज हेंब्रम के नेतृत्व में चले अभियान में 8 वाहनों को जब्त किया गया, छह ऑटो व दो छोटे मालवाहक शामिल हैं। इन सभी वाहनों के कागजात जांच के दौरान फेल मिले। पांच वाहनों को जुगसलाई और तीन वाहनों को साकची थाने में जब्त कर रखा गया है। 10 वाहनों पर ऑनलाइन लगभग 57, 000 रुपये जुमार्ना लगाया गया। जांच के दौरान वाहनों के फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण, टैक्स आदि कागजातों की सघनता से जांच की गई। मोटरयान निरीक्षक ने सभी वाहन मालिकों को ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स फिटनेस, प्रदूषण, इंश्योरेंस जैसे तमाम कागजात अपडेट रखने और बस और ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए ड्रेस कोड में ही वाहनों का परिचालन करने को कहा है।

ड्राइविंग के क्षेत्र में दो तरह से कॅरियर बनाया जा सकता है। मसलन, आप स्वयं के व्यवसाय के स्वामी और चालक हो सकते हैं। इसके लिए आप ओला और उबर के तहत पंजीकृत कुछ टैक्सी प्राप्त करें और इस उद्योग के माध्यम से भी अच्छी कमाई करें।

कॅरियर के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है ड्राइविंग

ड्राइविंग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कॅरियर बनाने के बारे में शायद ही कोई युवा सोचता हो। यकीनन यह कोई फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप इसे एक कॅरियर या व्यवसाय के रूप में देखते हैं तो इसमें भी आपके विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा कॅरियर ऑप्शन साबित हो सकता है, जो बहुत अधिक पढ़े-लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी आमदनी करके एक बेहतर जिन्दगी जीना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ड्राइविंग के क्षेत्र में कॅरियर बनाकर आप किस तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं-

ऐसे बनाएं कॅरियर

कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि ड्राइविंग के क्षेत्र में दो तरह से कॅरियर बनाया जा सकता है। मसलन, आप स्वयं के व्यवसाय के स्वामी और चालक हो सकते हैं। इसके लिए आप ओला और उबर के तहत पंजीकृत कुछ टैक्सी प्राप्त करें और इस उद्योग के माध्यम से भी अच्छी कमाई करें। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इस स्थिति में आप कुछ ओला व उबर आदि में बतौर कार चालक अपने कॅरियर की शुरूआत कर सकते हैं।

योग्यता

यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसके लिए किसी खास प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता हो। आपको बस एक वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है और फिर कई ड्राइविंग स्कूल हैं जो आपको अपने आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे। आप वहां से ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

अगर आप सच में अपने कॅरियर को ग्रोथ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपमें कुछ स्किल्स का होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको बेहद अच्छी तरह से कार ड्राइव करनी आनी चाहिए। यह आपके कॅरियर के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त है। इसके अलावा आप जिस शहर में हैं, वहां की सड़कों की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वैसे इन दिनों जीपीएस के जरिए भी रास्तों के बारे में पता लगाया जा सकता है। वहीं आपमें बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना भी बेहद आवश्यक है। सारा दिन आपकी गाड़ी में कई कस्टमर आएंगे, आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है।

संभावनाएं

इस क्षेत्र में कॅरियर ग्रोथ काफी अच्छी है। सबसे पहले तो आप ओला व उबर के अलावा कई ड्राइविंग कंपनियों में बतौर ड्राइवर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में बतौर टेनर भी काम कर सकते हैं और दूसरे लोगों को कार चलाना सिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पर्सनल कार ड्राइवर की जरूरत होती है, आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। वहीं खुद भी कार या टैक्सी लेकर उसे ड्राइव कर सकते हैं। इस तरह आप खुद ही मालिक बन सकते हैं।

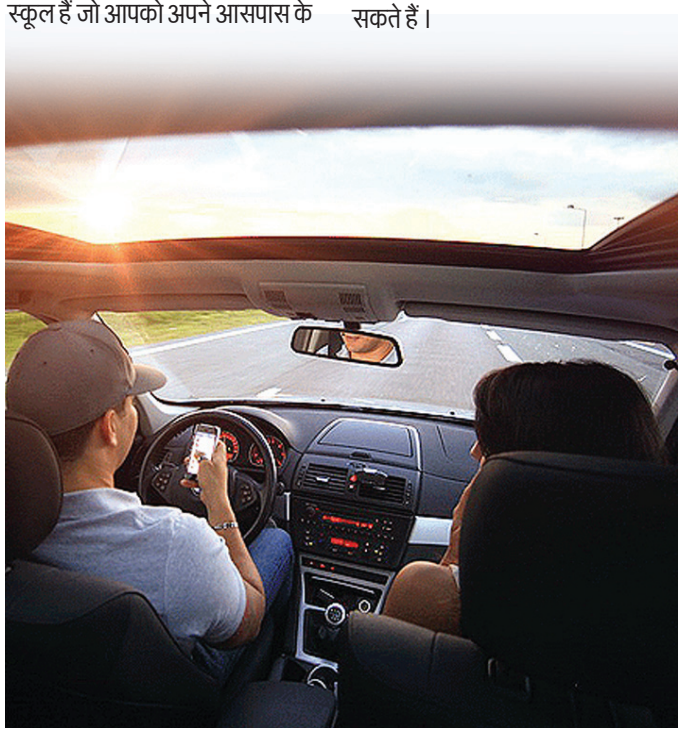

एक अच्छा मिक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए अच्छा श्रोता होना व फ्रेंडली होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा एक्यूरेसी, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्गेनाइजेशन स्किल्स, एनर्जेटिक, फलेक्सिबिलिटी, टीमवर्क, व क्रिएटिविटी जैसे गुण आपके काम को आसान बनाते हैं।

लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो मिक्सोलॉजी में देख सकते हैं अपना कॅरियर

अगर आप उनमें से हैं, जिन्हें नौ से पांच की जॉब करना अच्छा नहीं लगता। आप अपनी लाइफ में लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे में मिक्सोलॉजी के क्षेत्र में अपना कॅरियर देख सकते हैं। यह एक बेहद ही डिफरेंट कॅरियर ऑप्शन है। एक मिक्सोलॉजिस्ट एक व्यक्ति है जो कॉकटेल और मिश्रित पेय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मादक पेय और अन्य सामग्री को मिलाता है। आमतौर पर लोग मिक्सोलॉजिस्ट को बारटेंडर ही समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। बारटेंडर केवल बार में होते हैं और केवल पहले से मौजूद डिंक्स को ही बनाते हैं। जबकि मिक्सोलॉजिस्ट कई नए तरह के कॉकटेल बनाता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको इस कॅरियर के बारे में बता रहे हैं-

क्या होता है काम

एक मिक्सोलॉजिस्ट का काम बारटेंडर की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। वे कई तरह की डिंक्स को मिक्स करके एक नया पेय पदार्थ बनाने के अलावा, बार को आर्गेनाइज करना, कस्टमर्स को नए डिंक्स के बारे में बताना और उन्हें एंटरटेन करना, नए पेय पदार्थों का सुझाव देना और मेन्यू में कुछ नए पेय पदार्थों को शामिल करना होता है। यह एक ऐसी जॉब है, जिसमें आप हर दिन कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और खुद को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि यहां पर काम के कोई निश्चित घंटे नहीं होते।

स्किल्स

कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि एक अच्छा मिक्सोलॉजिस्ट बनने के लिए अच्छा श्रोता होना व फ्रेंडली होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा एक्यूरेसी, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्गेनाइजेशन स्किल्स, एनर्जेटिक, फलेक्सिबिलिटी, टीमवर्क, व क्रिएटिविटी जैसे गुण आपके काम को आसान बनाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए किसी निश्चित डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। आपके स्वाद की समझ ही आपको आगे लेकर जाती है। हालांकि, ज्यादातर कंपनियां ऐसे मिक्सोलॉजिस्ट को पसंद करती हैं जिनके पास बारटेंडिंग लाइसेंस होता है। उम्मीदवार किसी भी कंपनी में अल्पकालिक भुगतान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

संभावनाएं

यकीनन यह एक अलग कॅरियर क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप बार या रेस्टोरेंट के अलावा, क्लब, पब, होटल, टैवर्न आदि में बेहद आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां फूड एंड बेवरेज शो या फिर कई मार्केटिंग इवेंट्स में अपनी सर्विसेज देने के लिए भी मिक्सोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। इस तरह के इवेंट्स में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

आमदनी

एक मिक्सोलॉजिस्ट की सालाना पूरी तरह से उस क्लब / रेस्तरां / बार पर निर्भर करेगा जिस पर वह काम कर रहा है। फिर भी शुरूआती दौर में आप दो से तीन लाख रूपए सालाना आसानी से कमा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, लखनऊ
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोलकाता
- इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, अहमदाबाद
- नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा
- इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, मुंबई
- इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी- एप्लाईड नुट्रीसन, कोलकाता
- सेंटमेरी कॉलेज, बैंगलोर
- इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, शिमला

कैसे बनें लेखपाल? जानें योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सैलरी व सभी जानकारी

लेखपाल राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। लेखपाल को कुछ राज्यों में पटवारी, पटेल, कारनाम अधिकारी, शानबोगरु आदि नाम से जाना जाता है। यह एक सरकारी नौकरी है और इसमें जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ जैसे लाभ मिलते हैं।

आजकल अधिकतर युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरुरी नहीं है।

आज हम आपको बताएंगे कि आप लेखपाल कैसे बन सकते हैं -

लेखपाल राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। लेखपाल को कुछ राज्यों में पटवारी, पटेल, कारनाम अधिकारी, शानबोगरु आदि नाम से जाना जाता है। यह एक सरकारी नौकरी है और इसमें जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ जैसे लाभ मिलते हैं। आजकल युवाओं में इस पद की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेखपाल बनने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू देना होता है।

लेखपाल दो तरह के होते हैं - राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल आवासीय और व्यावसायिक जमीन से जुड़े काम देखते हैं और राजस्व लेखपाल आवासीय और व्यावसायिक जमीन से जुड़े काम देखते हैं।

योग्यता

- आपको किसी भी स्ट्रीम से बारहवीं पास होना चाहिए।
- मिनिमम परसेंटेज की कोई शर्त नहीं होती।
- उम्मीदवार के पास कम्प्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

आयु सीमा

लेखपाल बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष और 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाती है।

लेखपाल बनने की परीक्षा

लेखपाल बनने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू ये दो चरण होते हैं। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होती है। इसके लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। परीक्षा में हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्राम समाज और विकास के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सेक्शन में 25-25 प्रश्न होते हैं। लेखपाल की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, हिंदी सामान्य गणित और सामाजिक जीवन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर जो भी मार्क्स मिलते हैं उसी के आधार पर लेखपाल को चुना जाता है।

सैलरी

एक लेखपाल की सैलरी 5200-20200 रूपए प्रतिमाह पे-ग्रेड के अनुसार होती है। लेखपाल एक क्लेरिकल पोस्ट है जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है।

योग्यता

- आपको किसी भी स्ट्रीम से बारहवीं पास होना चाहिए।

टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर कमा सकते हैं लाखों

साफ-सफाई का खास ध्यान रहे और खाना बनाने से लेकर टिफिन डिलीवरी करने वाला व्यक्ति भी नीट और क्लीन रहे। साथ ही टिफिन बॉक्स में बेहतर क्वालिटी का हो, ताकि थाने के संदर्भ में अच्छी राय बने। टिफिन बॉक्स में खाना पैक करते समय इधर-उधर नहीं गिरना चाहिए।

कोरोनावायरस अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इस दौर में कई जमे जमाए बिजनेस और दूसरे प्रोफेशनों की कमर टूट चुकी है। कई लोगों की इस आपदा में नौकरी गई है तो कई लोगों का बिजनेस चौपट हुआ है। सबसे अधिक असर पड़ने वाली इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्री पर निश्चित रूप से बड़ा असर पड़ा है। होटल, ढाबे जहां पर लोग इकट्ठे होकर खाना खाते थे, वहां बिजनेस जबरदस्त ढंग से प्रभावित हुआ है। पर लोगों की खाना खाने की जरूरतें तो कम नहीं हुई हैं, ऐसे में कई जगहों पर सुरक्षित टिफिन सर्विस एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। आइए देखते हैं इसकी कहां कहां और किस प्रकार उपयोगिता है और आप इसके जरिए किस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं और किस प्रकार कमाई कर सकते हैं।

कारोबार को समझना जरूरी

ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, किंतु उसे समझना एवं प्रबंधित करने का ढंग आपको वास्तविक रुप से उसका फायदा दिलाता है। अगर आप किसी बिजनेस को ठीक ढंग से मैनेज कर पाते हैं तो भारी मुनाफा और अच्छी क्रेडिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। आखिर यूं ही तो आईआईएम से बड़े संस्थानों से निकले लोग सब्जी बेचकर या कोई छोटा मोटा रोजगार करके, या फिर खेती करके लाखों नहीं कमाते हैं? उनके कमाने के उदाहरणों से प्रबंधन के गुणों को सीखना जरूरी है।

कारोबार को प्रबंधित करने से पहले कारोबार को समझना और ग्राउंड वर्क करना जरूरी है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हों, आस पास अगर कोई टिफिन सर्विस चलती है तो उसके पास खुद एक ग्राहक बनकर जाएँ और देखें कि वहां पर किस प्रकार से आपको टिफिन दी जाती है, उसके रेट क्या है, सब्जी इत्यादि की वैरायटी क्या है, अलग-अलग दिनों में वेज और नॉनवेज का कॉम्बिनेशन क्या है? इतना ही नहीं, खाने की क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी की टाइमिंग इत्यादि किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, इन सब बातों को जब एक ग्राहक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसकी बारीकियां समझ आ जायेंगी।

कस्टमर मैनेजमेंट और मार्केटिंग

यह एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब आप एक कारोबार को समझ लेते हैं और ग्राउंड वर्क कर लेते हैं तो आपके सामने बड़ी चुनौती आती है कि कस्टमर आप किस प्रकार से ढूँढें? तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप खुद कैनवा जैसी ऑनलाइन सर्विस का प्रयोग करके अपनी टिफिन सर्विस का बैनर बना लें और व्हाट्सएप पर शेयर करें, खासकर उन कांटेक्ट में, जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं। शुरुआत में अगर आप के जानकार और आपके परिचित पहले ग्राहक बनते हैं, तो यह सबसे उत्तम होगा। एक तो ऑलरेडी वह आपको जानते हैं और दूसरे शुरू में विश्वास बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। यह कार्य व्हाट्सएप पर आप आसानी से कर लेंगे, किंतु सिर्फ जानकारों में आप यह कार्य बढ़ा नहीं पाएंगे। कारोबार बढाने के लिए आपको पंपलेट छपवाने पड़ेंगे और आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर करना पड़ेगा। वह हॉस्टल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, या कोई लोकलिटी हो सकती है। कस्टमर जब आपके बनने लगेंगे, तो उसको प्रबंधित करने में और क्वालिटी देने में आप चूक ना करें। ध्यान रखें, यह 21वीं सदी है और यहां पर जितनी बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस आप देंगे, आपके ग्रो करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कम लागत के लिए पहले एकाध कस्टमर से ही शुरू करें, और अनुभव के साथ महीने बाद कारोबार को गति दें।

ध्यान रहे कि यह बिजनेस ना केवल शहर में, बल्कि छोटे-छोटे कस्बों और यहां तक कि गांव तक में चलने लगा है। गांव में कई घरों में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो अकेले होते हैं। उनके बच्चे दूर शहरों में रोजी रोटी के लिए गए होते हैं, तो उनके लिए भी यह बेहद उपयोगी सर्विस है। ऐसे में निश्चित रूप से आपको इससे पुण्य और पैसा दोनों मिल सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

- साफ-सफाई का खास ध्यान रहे और खाना बनाने से लेकर टिफिन डिलीवरी करने वाला व्यक्ति भी नीट और क्लीन रहे। साथ ही टिफिन बॉक्स में बेहतर क्वालिटी का हो, ताकि थाने के संदर्भ में अच्छी राय बने। टिफिन बॉक्स में खाना पैक करते समय इधर-उधर नहीं गिरना चाहिए।
- मेन्यू अपडेट करते रहें। साथ ही ध्यान रखें कि स्वाद के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर के हेल्थ से समझौता हो जाए। कल्पना करें कि अगर कोई खाना खाने के बाद कस्टमर का पेट खराब हो जाता है या उसे अन हेल्दी फील होता है तो आप अपने ग्राहक खो देंगे। हां! स्वाद के लिए अपने मैन्यू में आप कोई मिठाई या दूसरी चीजें अपडेट करते रह सकते हैं।
- कस्टमर के फीडबैक के आधार पर किसी दिन उसकी पसंद का मैन्यू जरूर बना सकते हैं। त्यौहार इत्यादि के दिन पूरी या ऐसी दूसरी लोकल डिश कस्टमर को टेस्ट करा सकते हैं, पर यह कस्टमर के फीडबैक के आधार पर ही होना चाहिए।
- समय का पालन बहुत जरूरी है। अगर सुबह ब्रेकफास्ट 8 :00 बजे पहुंचाते हैं, तो यह किसी हालत में 8 से लेट नहीं होना चाहिए, बहुत पहले भी नहीं होना चाहिए। समय पर डिलीवरी आपके बारे में एक बेहतरीन राय कायम करेगी। अगर किसी कारण वश देरी होने की सम्भावना है तो व्हाट्सअप या कॉल पर कस्टमर को अपडेट जरूर कर दें।

अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति ज्यादा खतरनाक

ललित गर्ग

खतरा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों को नहीं है। खतरा हमारी संस्कृति को है, हमारी सांस्कृतिक एकता को है, जो हमारी हजारों वर्षों से सिद्ध चरित्र की प्रतीक है। जो युगों और परिवर्तनों के कई दौरों की कसौटी पर खरा उतरा है। कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक है, तो इस सच्चाई को स्वीकार करके रहना, अब तक हम क्यों नहीं सीख पाए?

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पहली बार 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं समाज को जागृत करने हेतु मनाया जाता है। इस साल थीम 'विविधता और समावेश का जश्न मनाना' है। इसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यकों की समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि अल्पसंख्यक के अधिकार सिर्फ. आकांक्षाएं नहीं हैं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए लोगों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक व्यावहारिक तरीका भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भारत में, इस दिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को जीवंतता प्रदान करने का दिवस है। भारत में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के गैर-भेदभाव और समानता के अधिकारों की गारंटी के प्रयास सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिन, देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान खींचा जाता है। लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं।

भारत 'लोकतंत्र की जननी' कहलाता है, यहां के लोकतंत्र को खुबसूरती प्रदान करने के लिये भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई उपक्रम एवं प्रयोग करता है। सरकार उन लोगों का गंभीरता एवं समानता से ख्याल रखती है जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों सहित उनकी जाति, संस्कृति और समुदाय के बावजूद आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र में अलग-अलग जातीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह होते हैं। भारत में अनेक अल्पसंख्यक समुदाय है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की, जो संविधान और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में दिए गए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अल्पसंख्यकों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के मकसद से मनाया जाता है। हालांकि, कानूनी रूप से भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के कई प्रावधान अनुच्छेद 29, 30 आदि हैं। अल्पसंख्यक शब्द अल्प और संख्यक दो शब्दों से बना है। जिसका मतलब दूसरों की तुलना में कम संख्या होना है। भारत में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं। जरूरत है कि अल्पसंख्यकों को नहीं बांटें और सत्य को नहीं ढकें।

लोकतंत्र भारत की आत्मा है और उसकी रगों में लोकतंत्र रचा-बसा है। यहां सभी को समानता से जीने का अधिकार है, जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण एवं अधिकारों पर बल दिया है तभी उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप पर मोदी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र या भू-भाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर बने संविधान के आधार पर चलती है तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 'सबका' शब्द में सभी अल्पसंख्यक वर्ग को सम्मिलित करने का भाव है, मोदी सरकार ने अपने नए नारे के साथ ये एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी विश्वास अर्जित करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। तीन तलाक के विरुद्ध कानून लाकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बहुसंख्यक समाज के महिला के बराबर बताने की कोशिश ऐसा ही प्रयास है।

भारत की माटी ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' का उद्घोष करके सभी प्राणियों के सुखी एवं समृद्ध होने की कामना की है। यहां अल्पसंख्यकों के साथ इसी उद्घोष की भांति उदात्तता बरती जाती है। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि किसी राष्ट्र की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।' इस दृष्टि से आजादी के बाद की सभी सरकारों ने अल्पसंख्यकों के साथ उदात्त एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के लिये अल्पसंख्यकों को गुमराह किया है, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा किया है। जिससे भारत के लोकतंत्र पर लाल और काले धब्बे लगते गये हैं। इन्हीं संकीर्ण एवं साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाले दलों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की बजाय उनको वोट बैंक मानकर उनके वास्तविक अधिकारों की अनदेखी की है। ऐसे राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, कहकर उन्हें उकसाया है, राष्ट्र की मूलधारा से अलग-थलग करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की अनेक बहुआयामी योजनाओं एवं नीतियों को लागू कर इन तथाकथित नेताओं की जुबान पर ताला लगा दिया है। सच कहा जाये तो देश में अल्पसंख्यक खतरे में नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाले खतरे में हैं। भारत विविध संस्कृतियों और समुदायों का देश है, यही इसका सौन्दर्य है। एक या अधिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और जबरन आत्मसात करने से समृद्ध और ऐतिहासिक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का नुकसान हो सकता है जिन्होंने सदियों से भारत में अपनी विरासत संभाली है। विशिष्ट भारतीय समुदायों की सांस्कृतिक रूप से विविध पहचान को केवल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही बरकरार रखा जा सकता है। भारतीय सामाजिक प्रथाओं में प्रत्येक संस्कृति और धर्म के प्रति सहिष्णु और सर्व-समावेशी रवैया शामिल है। भेदभाव, जबरन आत्मसातीकरण एवं धर्म-परिवर्तन समुदायों को खतरे में डालता है और भारतीय समाज के समग्र सार एवं उसके मूल स्वरूप को प्रभावित करता है। भेदभाव नफरत का सबसे खराब एवं वीभत्स रूप है। लोगों के एक समूह के खिलाफ उनकी भाषाई या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर हिंसक कार्रवाई करना किसी व्यक्ति के विवेक के लिए हानिकारक है।

खतरा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों को नहीं है। खतरा हमारी संस्कृति को है, हमारी सांस्कृतिक एकता को है, जो हमारी हजारों वर्षों से सिद्ध चरित्र की प्रतीक है। जो युगों और परिवर्तनों के कई दौरों की कसौटी पर खरा उतरा है। कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक है, तो इस सच्चाई को स्वीकार करके रहना, अब तक हम क्यों नहीं सीख पाए? देश में अनेक धर्म के सम्प्रदाय हैं और उनमें सभी अल्पमत में हैं। वे भी तो जी रहे हैं। उन सबको वैधानिक अधिकार हैं तो नैतिक दायित्व भी हैं। देश, सरकार संविधान से चलते हैं, आस्था से नहीं। धर्म को सम्प्रदाय से ऊपर नहीं रख सके तो धर्म का सदैव गलत अर्थ निकलता रहेगा। धर्म तो संजीवनी है, जिसे विष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वोटों के लिए जिस प्रकार की धर्म की एवं अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलाई जा रही है और हिंसा को जिस प्रकार समाज में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, क्या इसको कोई थामने का प्रयास करेगा? राजनीति का व्यापार करना छोड़ दीजिए, भाईचारा अपने आप जगह बना लेगा, अल्पसंख्यक अपने आप ऊपर उठ जायेगा।

संपादकीय

बदलते अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर की जा आपत्ति पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को इवीएम का रोना बंद कर, चुनाव नतीजों को कुबूलना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, जब आपको संसद में सौ से ज्यादा सदस्य मिलते हैं तो इसे जीत के रूप में उत्साहित होते हैं। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए तो पलट कर उन्हें दोष नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अगर ईवीएम समस्या है, तो आपको लगातार समस्या होनी चाहिए। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में अब्दुल्ला ने क्रांगेस के खिलाफ जाते हुए नये संसद भवन की तारीफ की। उनके विचारों से स्पष्ट है कि उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरारें आ रही हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल करते हुए कहा कि संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के कारण उसे लोक सभा व राज्य सभा दोनों जगह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी मिली है। इस पर दूसरे दल दावा नहीं कर सकते। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख दल सपा व टीएमसी अड़ानी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में साथ नहीं आए। मायावती एक देश-एक चुनाव को लेकर सरकार के पक्ष में आ चुकी हैं। उधर गठबंधन में ममता बनर्जी को नेतृत्व की कमान देने जैसी बातें भी जोर-शोर से उठ रही हैं। जिसका समर्थन लालू यादव भी कर चुके हैं। अब अब्दुल्ला के भाजपा के सुर में बोलने को इसी फूट से जोड़ा जा सकता है। भले ही वह इसे अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण कह रहे हैं। केंद्र सरकार भी विपक्ष द्वारा इवीएम पर उंगली उठाए जाने पर यही दलील देती है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़.कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। गठबंधन की राजनीति के अपने कुछ कायदे हैं, कांग्रेस जिनकी अनदेखी करती रही है। उसे बिखरने से बचाने की उम्मीद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कहा है कि कांग्रेस को नेतृत्व का मोह छोड़ना होगा। अय्यर ने कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए सभी दलों को उचित सम्मान देने की भी सलाह दी। मोदी को चुनौती देने और सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक-जुट रहने के प्रयास कमजोर पड़ते जा रहे हैं। संसदीय चुनाव में इस गठबंधन ने मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देकर काफी उम्मीदें बढ़ा ली थी। जो हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक काफूर हो गई। यदि कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला तो सहयोगी दलों की यह अनदेखी उसको भारी पड़. सकती है।

चिंतन-मनन

अनुशासन का पाठ

गुरु अंबुजानंद के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उनका आश्रम लंबे समय से चल रहा था। अब चूंकि अंबुजानंद काफी वृद्ध हो गए थे, गुरुकुल चलाना उनके लिए कठिन हो रहा था। वह अपने शिष्यों में से ही किसी एक को गुरुकुल का सारा कार्यभार सौंपना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने 18 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, आप सभी प्रतिभाशाली, मेहनती और ईमानदार हैं। यदि मैं आपको शिक्षा के लिए किसी विशेष क्षेत्र में नियुक्त करना चाहूं तो आप कौन-कौन से क्षेत्र को चुनना चाहेंगे?

यह सुनकर सभी शिष्य कुछ देर सोचते रहे और फिर 17 विद्यार्थियों ने अपने-अपने मनपसंद क्षेत्रों के नाम गुरु को बता दिए। अठारहवां शिष्य आयुष अभी तक कुछ सोच ही रहा था। उसे चुप देखकर गुरु ने पूछा, बेटा आयुष, तुमने अपने लिए किसी क्षेत्र का चुनाव नहीं किया? गुरु की बात सुनकर आयुष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैंने आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है। मैं आपके द्वारा सीखी गई शिक्षा को जन-जन तक फैलाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे किसी क्षेत्र विशेष का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर क्षेत्र में आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहूंगा।

हालांकि क्षेत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके दिए गए मूल्य या संस्कार का प्रसार, जो शास्त्रों से अलग है। मैं चाहता हूं कि लोग उसे जानें ताकि वे नैतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ हों। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो अनुशासन का पाठ हमें पढ़ाया है, उसे तो मैं विशेष रूप से सिखाना चाहूंगा। ज्ञान पाने के लिए व्यक्तित्व को एक खास सांचे में ढालना पड़ता है। आपने जिस तरह हमें ढाला है, मैं भी दूसरों को ढालना चाहूंगा। आयुष की बात सुनकर गुरु अंबुजानंद का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, आज से यह गुरुकुल तुम्हारी देखरेख में ही चलेगा।

नीतीश कुमार की यात्रा समाधान या सियासत, पर्दा उठ गया..!

श्रीराम सिंह

जब नीतीश केबिनेट ने 225 करोड़ राशि मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा के लिए स्वीकृत किया तब से ये डिबेट शुरू हो गई की इन यात्राओं से किसे क्या मिलेगा. इस यात्रा के पहले भी नीतीश कुमार 14 यात्राएं कर चुके हैं. उनका लोगों के जीवनस्तर पर कितना असर हुआ. इन सभी सवालों का जवाब खोजा जा रहा था इसी बीच नीतीश कुमार ने अपनी पंद्रहवीं यात्रा महिला संवाद यात्रा स्थगित कर दी. अब इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारे एयर मिडिया जगत में अलग अलग क्यास और संभावनाओं पर चर्चा छोड़ गई है. 2023 में नीतीश कुमार ने बिहार में अंतिम यात्रा समाधान यात्रा किया था. 5 जनवरी 23 को नीतीश ने पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू किया था, जो पटना में खत्म हुई. इस दौरान सीएम ने 28 दिन तक राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया था. नीतीश की इस यात्रा से जेडीयू कार्यकताओं का जोश आया तो वहीँ महागठबंधन में भी उत्साह बढ़ा. सीएम नीतीश कुमार जहां-जहां गए, वहां जेडीयू नेताओं और कार्यकताओं ने नीतीश के 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के लिए नारे लगाए और पूरा माहौल बना दिया था. हालांकि, सीएम खुद को पीएम कैंडिडेट मानने से बचने की कोशिश करते दिखे थे. लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपनी पंद्रहवीं यात्रा महिला संवाद का घोषणा किया. पिछली यात्राओं के नफा नुकसान पर डिबेट होने लगा है. आइये जानते हैं नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से बिहार की जनता, महागठबंधन, जदयू, भाजपा, एनडीए किसे कितना लाभ हुआ और 2024 के चुनाव में जेडीयू, महागठबंधन, भाजपा या एनडीए को कितना फायदा हुआ. सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देशभर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे रहे. कई राज्यों का दौरान किए और गैरभाजपा दलों को एक छत के निचे लाने में सफल रहे. वही इसके ठीक विपरीत यात्रा पर जेडीयू नेताओं का कहते रहे कि समाधान यात्रा का 2024 चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. मगर इस यात्रा से पार्टी ने नीतीश कुमार की छवि को सुधारने की कोशिश की. कुछ महीने पहले ही जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी-कांग्रेस और अन्य दलों के साथ सरकार बनाया था. उसके बाद फिर से कानून व्यवस्था, शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों पर सवाल उठने लगे थे. भाजपा लगातार बिहार में जंगलराज की वापसी के आरोप लगा रही थी. हलांकी कुछ महीने राजद के साथ सरकार चलाने के बाद छवि बदलने और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ही प्लान किया गया समाधान यात्रा निकालने का. जेडीयू कुछ हद तक इस अभियान में सफल भी हुई. वहीं इसका लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त फायदा हुआ. नीतीश ठीक एक साल के बाद फिर से एनडीए के साथ चले गए. हालांकी उससे ोाहले नीतीश कुमार ने एक सफल रणनीति का बीजारोपण जरूर कर दिया था जो इंडिया गठबंधन का रूप लिया. जिस अभियान में कई नेताओं ने प्रयास करने के बाद थक हार कर उम्मीद छोड़ दिया था उसे नीतीश ने सच कर के दिखाया. नीतीश कीमार की समाधान यात्रा से जनता को कितना फायदा हुआ इस बात से ज्यादा चर्चा यात्रा मे जुटने वाली भीड़ और उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उजस्थिति की थी. क्योकि इस भीड़ में नीतीश कुमार और जदयू के भविष्य को स्थायित्व देने वाला वोट दिख रहा था. हर जगह महिलाओं की लंबी कतार और दीवारों पर जीविका योजना के बैनर और पोस्टर बता रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए यह योजना काफी अहम है. जीविका योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में मूल रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर नीतीश ने महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए सफल प्रयास किया. इस तरह से नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मिलने वाले फीडबैक को खासा महत्व देते रहे हैं. बिहार में जीविका योजना से करीब डेढ़ करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं. यानि नीतीश कुमार ने होने लिए सबसे मजबूत और सुलझे हुए वोट बैंक का इंतजाम कर लिया है. यही कारण है की पूरी राजनीति इधर से उधर हो जाए और नीतीश कुमार का 15 प्रतिशत वोट टस से मस नहीं होता है. बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि महिलाओं के जरिए योजना चलाने से हर परिवार तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच आसानी से हो जाता है. बिहार के ग्रामीण इलाके में इसका बहुत असर भी हुआ है. महिलाएं न केवल आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि जीविका के जरिए दहेज प्रथा, शिक्षा और बाकी कई अहम मुद्दों पर सीधा संवाद से सफलतापूर्वक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. हर नीति और रणनीति की सफलता को नीतीश कुमार महिलाओं के माध्यम से आसानी से सफल कर लेते हैं. यात्रा के दौरान हाथों में बैनर और पोस्टर लिए महिलाएं शराब का विरोध और शराबबंदी का समर्थन करती नजर आती हैं. तो वहीं गाना बजाना, नृत्य और नाटक के माध्यम से नीतीश कुमार की नीतियों का मंचन कर उसे सहजता से समझाने में भी सहयोग करती हैं. महिलाएं खुल कर स्वीकार करती हैं, पहले हम घर में बंद थे. बाहर नहीं निकलते थे. कोई हमारी कद्र भी नहीं करता था. अब हम ग्रुप से जुड़ कर काम करती हैं. हमारा सम्मान बढ़ा है और आत्मनिर्भर भी हुए हैं. महिलाओं का कहना है, नीतीश कुमार ने महिलाओ के लिए बहुत कुछ किया है. विकास के लिए महिलाओं का साथ बहुत जरूरी है. महिलाओं

को नीतीश जी के राज में बहुत सम्मान मिला है. जिस तरह नीतीश कुमार 2005 में जब पहली पारी में असफल हुए तो उन्होंने यात्रा के माध्यम से आम लोगों तक अपनी बात और भावनात्मक लगाव का फैसला किया. नीतीश का यह फैसला बड़ा ही सफल रहा. उसके बाद जब जब नीतीश कुमार को लगा की कमजोर पड़ रहे हैं तो यात्रा पर निकल गए. हर यात्रा ने नीतीश कुमार को पिछली बार से ज्यादा मजबूत किया. इस बार भी नीतीश कुमार ने महिलाओं संवाद यात्रा के माध्यम से अपने कोर वोट बैंक को चुस्त दुरुस्त करने का बड़ा ही धाकड़ प्लान बनाया है. यात्रा को स्थगित करना या कहने तो आगे बढ़ा देने के पीछे भी नीतीश की कोई रणनीति होगी. 15 दिसम्बर से नीतीश कुमार ने संभावित यात्रा को स्थगित कर दिया. इसमें कोई सदा संदेश तो नहीं छीपा है? जब जब नीतीश कुमार ने बड़े फैसले लिए हैं तो माहौल जरूर अलग बन जाता है. हलांकी यता स्थगित होने का कारण खरमास बताया जा रहा है. पर जब तिथि पर विचार किया गया उस समय ध्यान नहीं दिया गया! वहीँ कहा जा रहा की 22 दिसंबर के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है. खरमास तो तब भी खत्म नहीं हो रहा. यानि कुछ तो है जिसकी पदेदारी है. नीतीश की माया नीतीश ही जाने. खरमास बात कहीं कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट तो नहीं होने वाला.

लोक सभा : प्रियंका के पहले भाषण ने जीता दिल

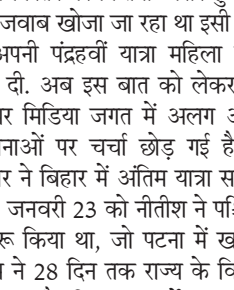

अमरेंद्र कुमार राय

प्रियंका गांधी से लोगों को शुरू से ही बहुत उम्मीदें रही हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मानते थे कि अगर प्रियंका राजनीति में उतरें तो अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तरह अपने सभी राजनीतिक विरोधियों की छुट्टी कर देंगी। वे उनमें इंदिरा गांधी की शक्ल देखते थे। वही आंखें वैसा ही नाक-नक्श; हू ब हू, लेकिन प्रियंका गांधी लंबे समय तक राजनीति में नहीं आई, आई भी तो अपने आप को सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक समेटे रहीं।

अब वो दिन भी आया जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई। उम्मीद की गई कि वे पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाएंगी। उन्होंने कोशिश भी की। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का ढांचा चरमरा गया है। उसे मजबूत करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने इस दिशा में पहल भी की। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सक्रियता भी बढ़ाई। लोग उनसे जुड़े भी, लेकिन चुनावों में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखा। बल्कि यूं कहें कि इसका उलटा हुआ। पिछले विधान सभा चुनावों में पार्टी करीब ढाई प्रतिशत वोटों पर सिमट गई। तब कहा जाने लगा कि प्रियंका को राजनीति में लाने में देर कर दी गई। बाद में तो यह भी चर्चा सुनी जाने लगी कि प्रियंका गांधी राज्य सभा के जरिये संसद में जाना चाहती हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जब जीत हुई और सरकार बनी तो चर्चा चली कि प्रियंका वहां से राज्य सभा में जा सकती हैं।

बाद में ऐसी ही चर्चा राजस्थान और तेलंगाना से भी जाने में हुई, मगर यह सब कयासबाजी ही साबित हुई। लोक सभा चुनाव में स्मृति ईरानी लगातार ताल ठोंक रही थीं और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए ललकार रही थीं। वे 2019 में राहुल को अमेठी से हरा चुकी थीं और उनके हौसले बुलंद थे। हालांकि जितने सर्वे हो रहे थे उन सबमें यही दिख रहा था कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी पर भारी पड़ रहे हैं, फिर भी राहुल या कांग्रेस ने ये साफ नहीं किया कि वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे ही। आखिर में जब सोनिया ने साफ किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वे चुनाव नहीं लड़ेंगी तो एक बार फिर चर्चा चली कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आखिर में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़े। राहुल अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से जीते। जब उन्होंने वायनाड छोड़ा तो प्रियंका वहां से चुनाव लड़ीं। वहां से वो चार लाख से ज्यादा वोटों से जीततीं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने लोक सभा में अपना पहला भाषण दिया। भाषण अच्छा था। सबने उन्हें सम्मान दिया। पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कम ही टोकाटोकी की। उनका भाषण काफी संतुलित और तथ्यपरक था। वे पूरी तैयारी से सदन में आई थीं और लिखकर ले आई थीं और उसे पढ़ रही थीं। लोगों ने उनके भाषण की तारीफ की फिर भी लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी जब बिना स्क्रिप्ट के भाषण देती हैं तो वो ज्यादा अच्छा और असरदार होता है। अभी चल रहे संसद के मौजूदा सत्र में लोक सभा में तीन लोगों के भाषण की ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रियंका गांधी ने करीब आधे घंटे भाषण दिया, राहुल गांधी ने करीब 26 मिनट जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घंटे भर से ज्यादा। सभी जानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी भी अच्छा बोलती हैं, लेकिन उनके भाषण की तुलना अभी तक मोदी के भाषण से नहीं हुई थी। राहुल कमजोर वक्ता हैं, ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन इस बार संसद में हुए भाषणों में जो तथ्य आये हैं उसने मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद टीवी पर उनके भाषण को एक खास समय में सिर्फ 26 हजार लोगों ने देखा, जबकि भाषण के मामले में कमजोर माने जाने वाले राहुल गांधी के भाषण को 86 हजार लोगों ने देखा। इस मामले में तो प्रियंका गांधी इन दोनों से ही बहुत आगे रहीं। उनके भाषण को नरेंद्र मोदी के भाषण से सात गुना ज्यादा लोगों ने देखा। उनके भाषण को एक लाख 89 हजार लोगों ने देखा।

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। यही वजह है कि उनका भाषण अच्छा होने के बावजूद उन्हें कम लोगों ने देखा, जबकि विपक्ष के नेता राहुल पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोग मान रहे हैं क

राहुल भले अच्छा भाषण न देते हों पर वे सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और लोगों की दिल से भलाई चाहते हैं। इसीलिए उनका भाषण कमजोर होने के बावजूद मोदी से तीन गुना ज्यादा लोगों ने देखा। प्रियंका संसद में पहली बार बोल रही थीं। शायद इस वजह से भी उनका भाषण बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। पर इतना तो तय है कि वे एक अच्छी वक्ता हैं। कांग्रेस को लोक सभा में अच्छे हिंदी वक्ता की कमी जो खल रही थी अब उसे पूरा करने के लिए वे आ गई हैं। प्रियंका भले दक्षिण भारत से जीतकर लोक सभा में पहुंची हैं पर इससे उत्तर भारत में कांग्रेस को नया बल मिल सकता है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Crossing the line on the judicial front

AN impeachment motion has been moved against Justice Shekhar Kumar Yadav of the Allahabad High Court over his remarks at a recent event of the Vishva Hindu Parishad (VHP). There is no chance that the move will succeed because the ruling dispensation is against it. Indeed, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has strongly supported Justice Yadav.There are reports that Justice Yadav has been asked by the Supreme Court Collegium to meet it. The latter has no legal authority to do so. Hence, he will be within the law to skip the meeting. However, if he does meet the Collegium, it can draw his attention to the Restatement of Values of Judicial Life, adopted by the Supreme Court in May 1997. It can advise him to observe them, but if he chooses to ignore them, it can really do nothing except recommend his transfer from the Allahabad HC. It is possible, though, that the government may not act on the recommendation.Thus, as matters stand, Justice Yadav virtually enjoys immunity for his remarks at the VHP function. Yes, there is one step the HC Chief Justice can take. He can decide not to allot judicial work to the judge on the ground that the comments have made him unfit to adjudicate cases. But that will require a very courageous Chief Justice in our contentious times.

Paragraphs 8 and 9 of Restatement of Values of Judicial Life read: “A Judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination. A Judge is expected to let his judgments speak for themselves. He shall not give interview to the media.”In the past, judges did not seek to attract attention either to themselves or their personal views on national affairs. They seldom gave lectures or participated in public functions. This was based on the sound principle that the public should have confidence that their decisions were based on the facts and the law and no other consideration. The cardinal and eternal essence of the dispensation of justice is that it must not only be done but also be manifestly done. Today, too, many judges of superior courts follow this principle and avoid the temptation of airing their views in public. However, if the feeling gains currency in the judiciary that there is nothing objectionable for judges to comment on issues such as the Uniform Civil Code (UCC) — a matter which may come up for adjudication — the present restraint exercised by most of the judges may get eroded to the detriment of the administration of justice in India. That will damage the national good.Justice Yadav not only spoke on the UCC but also did so in terms of rank communalism. All through his address, he spoke as a Hindu and addressed Muslims as a separate community. This violates the basic tenet of a judge: she/he will not distinguish between citizens on the grounds of religion either as individuals or as a group. It is particularly sad that Justice Yadav gave the go-by to the proud traditions of the Allahabad High Court, whose judges, even during the days of colonialism, strove to pursue the path of rectitude and reticence as well as fierce independence.

Justice Yadav may be suited for public life. He would have full freedom there to express his opinions, and if he is elected to a legislature, he can strive to ensure that these are converted into law. There is little doubt that political forces in the country that are supporting him may welcome him into their fold. They may find him an asset, for his VHP speech shows that he is a fluent public speaker who will be able to convey their beliefs succinctly to the public.I hope readers will forgive me for striking a personal note. My family members had a century-long association with the Allahabad HC as lawyers and judges. I moved away to the field of diplomacy, but have vivid recollections of the principles followed by my father, who retired as Chief Justice of this court. He told me that a judge should not only speak through his judgments but also confine those judgments to the law and facts of the case. He should not make obiter dicta, let alone use judgments to lecture society or point to national infirmities. That was the duty of other organs of the state.‘

Revival of India’s North Korean mission reflects strategic shift

Developments in the Korean peninsula are of greater strategic importance to India today than they were four years ago.

THE term 'Bangladeshis' in India has infiltrated our lexicon as "illegal" human beings. They have also become the most acceptable alibis for the political class to extract political mileage and distract unfavourable attention.he recent case in point is Delhi's Lieutenant-Governor VK Saxena, who announced a two-month special drive to identify and act against illegal Bangladeshi immigrants residing in the national capital. The Delhi police has started raids in slums across Kalindi Kunj, Shaheen Bagh and Jamia Nagar, where Rohingya refugees were provided land to set up camps.

Many in India like to believe that Rohingya are Bangladeshis despite sufficient knowledge that the ethnicity is among the most persecuted groups of Myanmar.It may not be a coincidence that this development came hours after the BJP demanded a CBI investigation into the alleged illegal settlement of Rohingya in Jammu and Kashmir. Chief Minister of the state Omar Abdullah has said the refugees should be deported, if at all, but they could not be made to starve and he would not let them die in the cold.Yet, I will not be surprised if this campaign to identify Bangladeshi "infiltrators" picks steam across other states. Let us not forget that we are upon another season of elections and, this time, for the national capital.Many would have forgotten that in mid-1992, Delhi had launched Operation Pushback to deport Bangladeshis. That was under the Congress government, which was responding to a belligerent Sangh Parivar dramatically heightening its pitch around unauthorised immigration. Assam had already scripted the threat of a silent demographic invasion by these impoverished, desperate, pitiable neighbours who were being pushed into India to seize Hindu territory.The template of Bangladeshi-phobia was a well-established eastern propaganda that the Sangh appropriated in its entirety. It was, however, willing to exclude the Hindu Bangladeshis as refugees who were escaping persecution. The same lens wouldn't apply to Rohingya at a later stage.Around the same time, the Sangh launched the slogan, 'Infiltrators Quit India', and forced the Congress to act against whom it considered infiltrators, setting the stage for an event that would change the political landscape of the country forever. By December, the crescendo had reached Ayodhya, resulting in the demolition of the Babri Masjid.The presence of illegal migrants from the neighbouring countries is not an unfamiliar piece of data. It is also well known that during the Congress regime, politicians have reportedly used these settlers as "vote banks". But there is no evidence yet or corroboration of the claim that millions of infiltrators have arrived to take over parts of this country.Instigated by the Sangh's growing voice against the infiltrators, the then Prime Minister Narasimha Rao rolled out an action plan against the Bangladeshis to counter the jingoism. It only added fuel to the propaganda. In September 1992, a group of 132 persons was identified as infiltrators and removed from the Seemapuri area of east Delhi.It is well known that all efforts by the government to arrest infiltration through the porous borders have proven ineffective. However, the build-up of such a campaign has been highly beneficial politically. The 1992 campaign, finally, provided the Sangh political legitimacy and made xenophobia and anti-Muslim rhetoric acceptable in public life.The current campaign launched by the bureaucratic arm of the BJP in Delhi has raises the suspicion of the beginning of a nationwide 'identification' drive that could serve as a precursor of another round of the National Register of Citizens (NRC).Though Assam provides the case study that the NRC is a wasteful exercise in detection, it has proven to be a worthwhile weapon to intimidate and harass Muslims. Manipulated by political parties, the acute fear of being rendered into a non-citizen has repeatedly triggered ethnonational projects across decades.In the politics of the Hindu right, the framing of migrants threatening the security of Hindu-India has become synonymous with Muslims in general.

The ongoing exercise is already on the lines of the NRC verification, something that Uttar Pradesh had initiated in 2019. The chorus then had gained momentum, with other states chiming in and Karnataka even constructing a detention centre.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, known for his anti-Muslim vocabulary, has floated the idea of a nationwide NRC in his recent election campaign in Jharkhand.Given India's poor neighbourhood policy that stood exposed after the fall of Dhaka this year, such rhetoric is bound to further deteriorate relations between the two countries, which are always on the edge with the NRC.

It will be interesting to see how this is going to play out with another Islamophobic campaign gaining ground: the claim of temples under mosques.The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 mandates that the nature of all places of worship, except the one in Ayodhya that was then under litigation, shall be maintained as it was on August 15, 1947.While one hoped the Ayodhya judgement would have closed this matter, more such suits have been filed in Varanasi and, more recently in Sambhal, where trial courts hastily ordered surveys of the mosques, resulting in a clash that killed four people.

This could well be a convergence of two distinctive sets of xenophobic projects that will set off a chain of low-intensity anti-Muslim campaigns working simultaneously, while stepping up the ante wherever political machinations are due.

While the detection and detention mechanism fits the concept of "the process is the punishment", the mosque surveys claiming buried temples aim to set right "historical wrongs", thus perpetrating the narrative of revenge against invaders who have looted the glorious past.

Perilous fast track

Dallewal’s extreme stand eclipsing big picture

THE life of farmer leader Jagjit Singh Dallewal, who is on a fast-unto-death, is precious — as rightly observed by the Supreme Court. So too are the lives of all protesters who are staying put at Shambhu and Khanauri borders in the bitter cold. And Dallewal himself has said that the lives of farmers pushed to the brink by flawed government policies are more valuable than his own. If every kisan’s life really matters, why have things come to such a pass? And why has the time-tested path of dialogue been abandoned?

Unfortunately, it was only after the apex court’s intervention that senior representatives of the Punjab and Central governments reached out to Dallewal. But it is unlikely that his extreme stand will force the Centre to accept farmers’ key demands, including a legal guarantee of MSP for various crops. After all, over 700 of them had died during a year-long agitation before the Modi government finally repealed the three farm laws. Ironically, Dallewal’s hunger strike and the efforts to dissuade him are eclipsing the big picture — the widespread agrarian distress fuelled by factors such as the debt burden, rising costs of farming and inadequate support for crop diversification.

The SC has urged farmers to adopt the Gandhian way of staging protests. The Mahatma considered fasting as a potent weapon in the Satyagraha armoury, but he made it clear that a Satyagrahi should do it only as the last resort — “when all other avenues of redress have been explored and have failed”. Leaders of farm unions still have the option of pressing the Centre to return to the negotiating table. The marathon talks between Union ministers and farmers’ representatives in February might not have produced a breakthrough, but that is no reason to snap lines of communication. A mutual climbdown is a must to save farmers’ lives as well as livelihood.

What porn has to do with the post-Nirbhaya world

Pornography can foster unhealthy attitudes that can escalate into sexual frustration and violence. Addressing this requires urgent government action.

ON December 16, 2012, the brutal gang-rape of a young physiotherapy student on a moving bus in Delhi became the turning point for India. The girl died, and the tragedy sparked protests and demands for justice, pushing for better legal protection for women.Named 'Nirbhaya', her death shook the country's conscience. The tragedy forced policymakers to confront the inadequacies in laws addressing sexual violence. Long-debated reforms were, finally, prioritised as the case became the catalyst for overhauling legal frameworks to ensure better protection, justice and accountability for crimes against women.Following the Nirbhaya tragedy, the Indian government passed the Criminal Law (Amendment) Act of 2013, expanding the definition of sexual violence to include stalking, voyeurism and acid attacks. It also increased the penalty for rape, including life imprisonment and death penalty for repeat offenders. Fast-track courts were introduced and an amendment in the 2015 Juvenile Justice Act allowed minors aged 16-18 committing heinous crimes to be tried as adults. A Nirbhaya Fund was created for the implementation of initiatives aimed at enhancing the safety and security of women, such as installing CCTVs at public places.

The 2017 Unnao rape case and the 2018 Kathua rape and murder case demonstrated the potential of fast-track courts to lead to convictions. But the 2020 Hathras gang-rape revealed that challenges still persisted in achieving impartial justice.Today, 12 years after the Nirbhaya case, despite various legal reforms, women face persistent sexual violence. In August this year, a doctor was raped and killed at a hospital in Kolkata, while a seven-month-old girl was brutally raped earlier this month, again in Kolkata. This tragic reality signals a profound societal failure.It is not easy to pinpoint any particular reason behind the continued sexual crimes against women and even babies. A complex interplay of social, cultural, economic and systemic factors is behind it — from the deep-rooted patriarchy perpetuating harmful gender norms to devaluing women as subordinates to men; from the lack of open conversations about healthy sexual relationships to the absence of comprehensive sex education; from delayed investigations, low conviction rates and insensitive handling of cases to under-reporting of such cases due to social stigma; from substance abuse to rapid urbanisation, migration and weakening of community ties; from social isolation and anonymity in urban settings to unemployment and economic inequalities. All these factors can create frustration and aggression, sometimes leading to acts of sexual violence.Another contributing factor is the rapid digitisation and low-cost or free accessibility of pornographic material. A study published in the 'Indian Journal of Public Health' points out that India, with 12 per cent of the websites devoted to pornography, ranks third in porn consumption globally. Excessive consumption of porn has become a pressing public health concern, with research pointing to its correlation with sexual crimes.

A study by the UK Government's Equality Office in 2020 found that though harmful attitudes toward women are influenced by multiple factors, a key reason was pornography. Many researchers consider it to be a significant contributor to harmful sexual beliefs and behaviours in high-risk individuals.Understanding this relationship requires the examination of pornography consumption. Viewing too much pornographic content leads to desensitisation. It makes the content mundane and commonplace, leading to increased exposure time and a quest for more hard-core content. It also leads to a detachment from reality and lack of differentiation between the real and the virtual.

Whether pornographic content affects sexual aggression has been debated for decades. Since complex multiple factors contribute to deviant behaviour, blaming pornography alone oversimplifies the issue and diverts attention from the systemic causes. However, one certainly cannot ignore pornography as a key factor.

Research on rape culture has focused on understanding the acquisition of attitudes, behaviours and norms associated with violence against women. While many of these factors are more influential than pornography, it is often pornography's interaction with these factors and their exacerbation that heightens its impact. Certain types of pornography, particularly those depicting violence or non-consensual acts, may normalise aggression and perpetuate misogynistic views.

Frequent consumption of such material can desensitise viewers to violence and blur the understanding of consent in a relationship. For individuals with a predisposition towards violent or harmful behaviour, pornography can act as a trigger, reinforcing these tendencies. Exposure to pornography that objectifies women can increase the acceptance of rape myths and play a significant role in shaping attitudes linked to the perpetuation of 'rape culture'.

The myths associated with rape promote the idea that rape is usually avoidable if certain precautions are taken. The onus of "don't get raped" is thrust upon women (as opposed to "don't rape" upon men). And, this self-protective ideal lends itself comfortably to blaming the victim and absolving the perpetrator.

Urgent government action is needed to address this menace. The steps required to be taken include the regulation of free pornographic websites and issuance of trigger warnings as also seeking proof of age for access to such sites and holding awareness campaigns and supervised discussions on consent and respectful relationships. Introducing media and digital literacy in educational institutions, adult education classes, institutions of open and lifelong learning and community and vocational education can further equip students to evaluate harmful content critically.As we honour Nirbhaya's memory, her legacy demands more than symbolic gestures. Strong laws must be enforced and efforts to inculcate gender sensitivity amongst all stakeholders must continue. Justice-focused narratives should dominate the media, countering misinformation and fostering accountability. The government should commission research studies to find reasons behind the persistence of rape cases. The transformation journey requires a collective effort towards creating a society where every citizen feels safe and no girl has to pay with her life and be named 'Nirbhaya' again.

NMDC share price falls over 6% today. Here's why

NEW DELHI Shares of NMDC Ltd. and other steel companies came under pressure on December 18 following the Karnataka government's proposal to tax mines and mining land, reported by CNBC.

National Mineral Development Corporation Limited bore the brunt of the sell-off, with shares dropping 6% to Rs 213.49 apiece by 12:30 pm, marking its steepest fall in 18 weeks. Other steel stocks, including JSW Steel and SAIL, also saw declines of 2% and 1.74%, respectively, as reports suggested a possible hike in duties on iron ore.

KARNATAKA'S MINING TAX BILL AND ITS IMPLICATIONS

The Karnataka Cabinet recently approved the Karnataka (Mineral Rights and Mineral Bearing Land) Tax Bill, 2024, aimed at levying taxes on mineral rights and mineral-bearing land. This decision is particularly significant for NMDC, as Karnataka accounts for 35% of its production.The proposed Bill allows for taxes ranging between Rs 20 and Rs 100 per tonne of minerals, which could generate annual revenue of Rs 4,207.95 crore for the state. Additionally, land-bearing mineral taxes are expected to add another Rs 505.9 crore annually.

The Bill comes after the Supreme Court's earlier approval for states to retrospectively collect mining taxes from 2005. Higher iron ore costs resulting from the tax are likely to affect the profitability of steelmakers and miners alike.

As Karnataka's proposed mining tax reshapes the cost structure for steel and mining companies, stakeholders and investors will closely monitor its implementation and broader implications for the sector.

Bumper debut for Mobikwik shares as stocks list at 59% premium on Dalal Street

NEW DELHI. Mobikwik shares made a bumper debut on the stock exchanges on Wednesday, listing at a premium of over 50%, making investors richer.

The shares of One Mobikwik Systems debuted on the BSE at Rs 442.25, marking a 58.51% premium over the issue price of Rs 279. On the NSE, the stock began trading at Rs 440, reflecting a 57.71% premium compared to the issue price.The allotment of shares for the initial public offering (IPO) of Mobikwik Systems Limited was finalised on Monday after having witnessed strong interest from investors.Mobikwik IPO was among the three IPOs that were open for bidding in the last week but received the most subscriptions. Mobikwik IPO bidding closed on December 13, 2024.

Mobikwik IPO saw an overall subscription of 119.38 times. Retail investors led the bidding process and the section was subscribed 134.67 times. Qualified Institutional Buyers(QIBs) section was subscribed 119.50 times, while Non Institutional Investors (NII) section received a bid of 108.95 times.

"The company's recent shift to profitability, coupled with the growing adoption of digital payments, boosted market confidence. However, sustaining this momentum would depend on its ability to maintain profitability and carve out a niche in the competitive fintech sector. Investors are recommended to book profits given the high listing gains, while those wanting to hold should set a stop loss at around Rs 400," said Shivani Nyati, Head of Wealth at Swastika Investmart Ltd.

ITC Hotel demerger from January 1, 2025

NEW DELHI. FMCG giant ITC Ltd has fixed January 1, 2025 as the effective date for the demerger of its hotel business after receiving an order from the National Company Law Tribunal (NCLT).In a regulatory filing, ITC said that the Kolkata Bench of NCLT had sanctioned the scheme of arrangement between ITC Ltd., ITC Hotels Ltd., and their respective shareholders, earlier this October."We advise that ITC Limited and ITC Hotels Limited have acknowledged that all the conditions specified in Clause 28 of the Scheme have been fulfilled and satisfied… the appointed date and the effective date of the scheme shall be the first day of the following month i.e. 1 st January, 2025, in accordance with clauses 5.1(iii) and 5.1(xvi) of the scheme, respectively," the company said in an exchange filing.In June 2024, ITC shareholders approved the demerger of the conglomerate's hotel business. About 99.6% of shareholders voted in favour of demerger, while just 0.45% voted against it.The board members of ITC had on August 14 last year approved the demerger of its hotel business.

Slower Q2 GDP growth temporary blip, will see healthy growth in coming quarters: FM Sitharaman

NEW DELHI. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has termed the second quarter GDP growth slowdown a temporary blip and expressed her confidence that the economy will see healthy growth in the coming quarters.Replying to a debate in the Lok Sabha on the first batch of Supplementary Demands for Grants, FM said India has seen "steady and sustained" growth and its GDP growth rate has averaged 8.3% in the last three years.

She reiterated that India continues to be the fastest-growing major economy in the world, and the credit for which goes to the people of India who are meeting their aspirations, and contributing to the economy.

"The real growth rate for Q1 and Q2 of this fiscal(FY25) has been 6.7% and 5.4%, respectively. At 5.4%, the Q2 rate is slower than expected...Q2 of this financial year has been a challenging quarter for India and most other economies of the world," she said.The finance minister further said there is no broad-based slowdown in the manufacturing sector. "A generalised slowdown in manufacturing is not expected, as it is restricted to few segments.

Sebi board may overhaul norms on SME IPOs, insider trading

The market regulator may raise the minimum application size for an SME IPO to Rs 2-4 lakh from the present Rs 1 lakh. The higher size will limit the participation of retail investors, who have been increasingly applying for such IPOs.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), in its board meeting scheduled on December 18, is likely to discuss and approve various norms, including those relating to initial public offer (IPO) by small and medium enterprises (SME), unpublished price sensitive information (UPSI) and regulatory framework for angel funds.The market regulator may raise the minimum application size for an SME IPO to Rs 2-4 lakh from the present Rs 1 lakh. The higher size will limit the participation of retail investors, who have been increasingly applying for such IPOs.

The SME IPOs have witnessed a surge in recent years particularly from 2022-23 onwards. Since the establishment of SME platforms, FY 2023-24 witnessed the highest number of SME public issues and highest SME fund raising with 196 IPOs tapping the market to mobilize more than Rs 6,000 crore. In FY2024-25 (till October 15, 2024), more than Rs 5,700 crore has been raised through 159 SME IPOs.With an increase in the number of SME issues, the rise in investor participation in such offerings have also seen a jump, causing concerns for SEBI. The applicant-to-allotted investor ratio has surged from 4 times in FY22 to 46 times in FY23 and 245 times in FY24.Sebi may increase the requirement of minimum allottees for an SME IPO to 200 for such public issue to be successful, from the present 50 allottees. In order to ensure that a promoter of an SME company continues to have certain skin in the game, SEBI may increase the lock-in on minimum promoter contribution (MPC) in SME IPO to 5 years from the existing three years.The regulator may allow an SME company to float an IPO only if the issue size is over Rs 10 crore and the operating profit is Rs 3 crore for at least any 2 out of 3 financial years preceding the IPO application.

Sebi board may also review the definition of Unpublished Price Sensitive

Information (UPSI) to bring about regulatory clarity, certainty and uniformity in compliance for the listed companies. UPSI refers to any information, relating to a company or its securities, directly or indirectly, that is not generally available. On becoming generally available, UPSI is likely to materially affect the price of the securities.The regulator may include restructuring/one-time settlement in relation to loans, initiation of forensic audit, action initiated by any enforcement authority against the listed company or senior management, fundraising and agreements control of the company in the definition of UPSI.As part of reviewing the regulatory framework for angel funds in alternative investment funds (AIF) regulations, SEBI may clear the proposal to allow only accredited investors to invest in angel funds. Such accredited investors will be required to meet commensurate net-worth criteria, which will be verified by a third-party accreditation agency.

Allowing accredited investors would allay concerns regarding investors without the necessary risk appetite, evaluating and making investments in start-ups through angel funds.The minimum investment limit by an angel fund in a start-up is likely to be reduced to Rs 10 lakh from Rs 25 lakh, and the maximum investment may be hiked to Rs 25 crore from the existing Rs 10 crore limit.

Vishal Mega Mart shares make strong market debut at 33% premium on D-Street

Vishal Mega Mart share price: The stock began trading at Rs 104, at a premium of 33% over its issue price of Rs 78.

NEW DELHI. Vishal Mega Mart shares made a bumper debut on the Dalal Street on Wednesday after the shares listed at a premium of over 33%.Vishal Mega Mart made an impressive debut on the NSE, surpassing market expectations by listing at a 33.33% premium to its IPO allotment price of Rs 78. The stock began trading at Rs 104, providing substantial returns for those who invested during the IPO. Following the strong opening, the Gurugram-based retail giant's market capitalisation climbed to Rs 46,891 crore.The allotment for shares was completed on December 16, 2024 after it garnered a good response from the investors, having been subscribed over 27 times after the 3-day bidding process which started on December 11.The company offered shares in the price band of Rs 74-78 per share, with a minimum lot size of 190 shares.

Established in 2001, Vishal Mega Mart is a prominent hypermarket chain in India, offering a wide variety of products. These include apparel, groceries, electronics, home essentials, and fast-moving consumer goods (FMCG). The company markets both its own private labels and products from well-known third-party brands, catering to diverse consumer demands.

"Given that this was a complete offer for sale (OFS), there are no direct benefits to the company, making it a play purely on market sentiment and its growth story in the retail sector. Investors are advised to book profits at this level, while those looking to hold should maintain a stop loss at around Rs 95," said Shivani Nyati, Head of Wealth at Swastika Investmart Ltd.

Rs 880 crore unclaimed: Is your LIC policy among them Here's how to check

NEW DELHI. A surprising revelation from the Life Insurance Corporation (LIC) has brought attention to unclaimed maturity benefits worth â‚¹880.93 crore for the financial year 2023–24.

According to Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary, who shared the data in Parliament, around 3.72 lakh policyholders failed to collect their maturity benefits during this period, reports PTI. If you think you might have missed out, here's how you can check and claim your unclaimed LIC policy amount.HOW TO CHECK UNCLAIMED LIC AMOUNTS

Policyholders or beneficiaries can check unclaimed amounts by visiting the LIC website (https://licindia.in/home). Here are the steps:Go to the 'Customer Service' section and select 'Unclaimed Amounts of Policy Holders.'

Enter the policy number, name, date of birth, and PAN card details.

Click on 'Submit' to view the details

Required details include the policyholder's name, policy number, date of birth, and PAN. LIC has also implemented various measures, including media campaigns and regular follow-ups by agents, to reduce unclaimed claims.

WHAT HAPPENS TO LONG-UNCLAIMED AMOUNTS?

If money remains unclaimed for over 10 years, it is transferred to the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF). These funds are utilised for senior citizens' welfare. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) mandates insurers to display unclaimed amounts of Rs 1,000 or more on their websites.Unclaimed amounts can arise due to litigation, rival claims, blocked policies, or policyholders being out of reach, such as residing abroad or delaying claims for pensions or annuities.

Unclaimed deposits are more than forgotten amounts; they reflect missed opportunities for financial security. LIC's efforts to streamline settlements and spread awareness aim to ensure rightful policyholders or beneficiaries receive their dues promptly.Checking your policy status regularly can save you from losing out on valuable benefits. Don't let your hard-earned money sit idle—claim it while it's still yours!

Sensex, Nifty open lower as cautious investors weigh global trends

NEW DELHI. Benchmark stock market indices opened lower on Wednesday after having incurred heavy losses in the past two trading sessions as cautious sentiment prevailed among investors.

The S&P BSE Sensex was down 15.56 points to 80,668.89, while the NSE Nifty50 lost 4 points to 24,332.00 as of 9:55 AM.Dr. V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services said that the near-term market construct has turned weak with FIIs turning sellers on rallies."The trend of FII buying in early December has proved to be, as feared, a flash in the pan. Yesterday's massive FII sell figure of Rs 6410 crores in the cash market indicates that more selling is in store on market bounces. The underlying reason for

the FII selling in India is the outperformance of US and the underperformance of India. While the S&P 500 is up 27.5% YTD, Nifty is up only 12% YTD. The fear is that this huge variation in relative performances may continue, given the strength of the US economy and the weakness in the Indian economy. The situation will change if leading indicators in India suggest recovery in GDP growth and corporate earnings in Q3," he addedGlobal markets are closely watching the Federal Reserve's decision, which is anticipated later today. The market has already factored in a 25 basis point rate cut, making the central point of interest the Fed's commentary accompanying the decision. Meanwhile, in the Indian market, a notable trend is emerging where the broader market is showing strong performance. Companies delivering positive results are being rewarded by investors, and foreign institutional investor (FII) selling does not appear to be a significant concern at the moment.

Gold import up on tariff cut, UAE pact

331% rise in imports of yellow metal to $15 bn in November resulted in trade deficit and pressure on the rupee.

NEW DELHI. Indians' love for gold has often gone against the country's financial health -- with a large part of the demand for the precious metal being fulfilled through imports.

The 331% year-on-year increase in gold imports to $15 billion in November has not only resulted in a record trade deficit during the month, it has also put pressure on the rupee, which has been shy away from the 85-a-dollar level. The unprecedented increase in gold imports has left many analysts clueless as they feel festive demand alone cannot explain

the jump in gold imports.According to Nomura, the rise in gold imports this November cannot be explained by festive demand alone, and "it represents a meaningful step up in gold purchases for reasons unclear to us."However, some analysts have come up with plausible reasons for the sudden increase. Gaura Sen Gupta, chief economist, IDFC FIRST Bank, and Ajay Srivastava, founder, Global Trade Research Initiative (GTRI), have partially attributed the import duty cut from 15% to 6% in the July budget to this increase in gold imports."The reduction of import tariffs from 15% to 6% in the last Budget, aimed at checking gold imports from Dubai, has further incentivised imports," says Ajay Srivastava of GTRI.

After reduction in import duty in July 2024, gold imports kept increasing month-on-month. In August, gold imports more than trebled to $10 billion from $3.1 billion in July.After a fall in September (to $4.4 billion) due to Pitru Paksh, the growth in gold imports resumed with $7.1 billion in October and $14.9 billion in November.

But there are other reasons as well for the country's gold imports bill to surge. Crisil believes high global prices have added to India's gold import bill. International gold prices of rose from $2,300 an ounce level in July 2024 to 2,700 levels in the first half of November. The prices on average hovered around $2,650 in November.

Ajay Srivastava of Global Trade Research Centre (GTRI)says the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), effective since May 1, 2022, has also contributed to the surge.

According to him, CEPA allows unlimited duty-free imports of gold, silver, platinum, and diamonds into India over the coming years. India's imports of gold and silver from the United Arab Emirates have surged by 210 percent, reaching $10.7 billion in 2023-24.

Supreme Court Sets Aside Death Penalty In Boy's Sexual Assault, Murder Case

New Delhi. The Supreme Court on Tuesday set aside the death sentence imposed on a convict in a sexual assault and murder case of a four-year-old minor boy in 2016, and substituted it with a 25-year jail term without remission.Holding the crime was diabolical, a bench comprising Justices B R Gavai, Aravind Kumar and K V Viswanathan, took note of the mitigating circumstances and observed it was not a case where the possibility of reformation was completely ruled out.The case does not fall in the rarest of rare category, the bench said.

Having regard to the nature of the offence, a sentence of imprisonment for a prescribed period without remission would alone be proportionate to the crime and also not jeopardise the public confidence in the efficacy of the legal system," it said, "a sentence of imprisonment for a period of 25 years without remission would be a just dessert".The apex court delivered its judgement on an appeal filed by convict Sambhubhai Raisangbhai Padhiyar challenging the Gujarat High Court's April 2019 verdict.The high court had confirmed the conviction and death sentence imposed on him by a trial court for the offences punishable under various sections of the IPC, including murder besides the Protection of Children from Sexual offences (POCSO) Act, 2012.According to the prosecution, Padhiyar kidnapped the four-year-old boy, sexual assaulted and murdered him in April, 2016, in Gujarat's Bharuch district."Without doubt, the crime committed by the appellant was diabolic in character. He enticed the innocent child by tempting him with ice-cream and brutally sodomised and murdered the four-year old. The appellant also mercilessly strangulated the deceased," the top court said.The mitigation investigation report filed before the apex court showed the appellant was 24-years of age at the time of incident, no criminal antecedents and hailed from a low

socio-economic household.

The bench said the report from the superintendent of Vadodara Jail indicated the appellant's behaviour in prison was completely normal and his conduct was good.

It further said the report from a mental health hospital indicated the appellant had no psychiatric problem at present."Considering the overall facts and circumstances, we hold that the present is not a case where it can be said that the possibility of reformation is completely ruled out. The option of life imprisonment is also not foreclosed," the bench said.It said though the case of the appellant fell short of the rarest of rare category, considering the nature of the crime, the court "strongly" felt a sentence of life imprisonment -- normally working out for 14 years -- would be grossly disproportionate and inadequate.

The top court's verdict noted the prosecution's case alleging the child was playing near his house when the accused took him on the pretext of getting him ice-cream, and later his mortal remains were found near bushes.

"The deceased, aged between three-and-a-half and four years, was a small child, just out of toddlerhood and at the preschool stage. This is very significant because when the appellant has from the neighbourhood of the house of the deceased taken the deceased one would expect that the small child would be brought back and dropped at the house," it said.

Goa Chief Minister's Wife Sues AAP MP For 100 Crore Over Job Scam Charge

New Delhi. Sulakshana Sawant, the wife of Goa Chief Minister Pramod Sawant, has filed a ? 100 crore defamation suit against Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjay Singh for allegedly naming her in a "Cash-for-Jobs Scam" in Goa during a press conference earlier this month.Sulakshana Sawant filed the defamation suit in the Civil Judge Senior Division Court in Bicholim, Goa, against Sanjay Singh.According to an official press note, the allegations claim that Sanjay Singh linked Sulakshana Sawant to a "Cash-for-Jobs Scam" in Goa, claiming she was involved in corrupt practices.

These statements were broadcast live on multiple national and regional news channels and shared widely on social media platforms like YouTube, where they have garnered significant views," said the allegations.The defamation suit asserts that these false accusations were made without any credible evidence, causing harm to Sulakshana Sawant's integrity and public image. The statements made by Mr Singh, according to the lawsuit, were not only damaging but were also broadcasted and shared extensively, amplifying the false allegations."The defamation occurred during a press conference where Sanjay Singh made direct accusations against Sulakshana Sawant's integrity and her involvement in the scam, thereby damaging her reputation," said the press note.

As per an official press note, the legal action sought by Sulakshana Sawant includes seeking ? 100 crores as damages for defamation, a permanent injunction against Sanjay Singh and his associates, restraining them from making or publishing defamatory statements, videos, or articles about her on any platform, including social media.Ms Sawant has also demanded a public apology from Sanjay Singh, clarifying the falsehood of his statements and the defamatory video, article.

She has also sought an injunction to prevent further defamatory statements by Mr Singh or his associates during the course of the suit.Further, Ms Sawant has requested the court to grant the costs of the suit and any other appropriate reliefs.As per the press note, the baseless and defamatory statements made by Sanjay Singh are "....Over the past 10 years, the Bharatiya Janata Party (BJP) government has been involved in corruption and bribery under the guise of job creation. Even the wife of Chief Minister Pramod Sawant has been named in the scandal, along with several of his ministers.""This is not a small issue -- it is a massive job scam involving corruption and bribery in Goa, with direct involvement from the Chief Minister and his ministers. The names of the Chief Minister's wife and various brokers have been revealed."This job bribery scam became even more serious when the then-Governor, Satyapal Malik, publicly stated that Chief Minister Pramod Sawant's wife was involved in the job scam, accepting bribes for jobs, committing corruption, and demanding money.""This clearly indicates that the Chief Minister of Goa and his entire family are involved in accepting bribes under the pretence of offering jobs."

High Court judge appears before Supreme Court over 'majority' remark: Sources

NEW DELHI. A controversy has erupted following remarks made by Justice Shekhar Kumar Yadav of the Allahabad High Court at an event organised by the Vishwa Hindu Parishad (VHP). The judge, who reportedly made statements endorsing the Uniform Civil Code (UCC) and allegedly commented on the Muslim community, appeared before the Supreme Court collegium on Tuesday to clarify his position, sources said.Justice Yadav's speech at the VHP Legal Cell's provincial convention in Allahabad, where he reportedly stated that laws should reflect the majority's will, triggered a political and judicial backlash.

Responding to the developments, the Supreme Court had, on December 10, sought details from the Allahabad High Court regarding the judge's remarks. On Tuesday, Justice Yadav travelled to Delhi and met with the collegium led by Chief Justice of India Sanjiv Khanna.According to sources, the collegium expressed concern over his public statements, advising him to exercise caution in his speeches and maintain the dignity of his constitutional office.Justice Yadav was reportedly reminded that casual remarks in public forums could harm the judiciary's credibility and emphasised the need for restraint, particularly on sensitive matters.In September 2021 also, Justice Shekhar Yadav made some observations on cows while hearing a case on their slaughter.

"Cows should be declared the national animal, and cow protection should be kept as a fundamental right of Hindus because when the culture and faith of the country are hurt, the country becomes weak," he had said.

Pitiable some retired high court judges get meagre pension: SC

NEW DELHI. The Supreme Court on Wednesday said it was "pitiable" that some retired high court judges were getting a pension ranging between Rs 10,000 and Rs 15,000."You cannot have a legal approach in every matter. Sometimes, you need to have a humane approach," observed a bench of Justices B R Gavai and K V Viswanathan."It is pitiable," the bench said, while noting that some retired high court judges were getting pension ranging between Rs 10,000 and Rs 15,000.The pleas raising issue concerning pension of retired high court judges was listed for hearing before the bench on Wednesday.Attorney General R Venkataramani mentioned the matter before the bench and requested that it be taken up for hearing in January. Venkataramani said the government would try to resolve the issue.

"It is better you persuade them that our intervention should be avoided," the bench observed.It said the matter would not be decided on individual cases and whatever the top court might lay down would be applicable to all the high court judges. The bench posted the matter for hearing on January 8.While hearing one of the pleas in the matter last month, the apex court had expressed "shock" that some retired high court judges were getting a meagre pension ranging between Rs 6,000 and Rs 15,000.

The bench was hearing a petition filed by a retired high court judge who said he was receiving a pension of Rs 15,000.The petitioner, who was elevated as a judge of the Allahabad High Court after serving as a judicial officer in the district court for 13 years, had claimed that the authorities had refused to consider his judicial service while computing the pension."If there are retired high court judges before us who are getting Rs 6,000 and Rs 15,000 as pension, it is shocking.How can that be?" the bench had remarked while hearing the plea.While hearing a separate plea in March, the apex court had said there cannot be any discrimination in computing the pensionary benefits of retired judges of high courts based on whether they were elevated from the bar or the district judiciary.

"We Have Polls All The Time": BJP MP Hema Malini On 'One Nation, One Election'

New Delhi. BJP MP and renowned actress Hema Malini on Tuesday voiced her support for the 'One Nation, One Election' bill, citing the benefits of synchronised elections. She emphasizes that frequent elections in India, unlike other countries, hinder her work as an MP due to the model code of conduct enforcement.

Ms Malini argues that simultaneous elections would conserve resources, which could then be allocated to vital sectors like education and health. This perspective resonates with concerns about the economic burden of frequent elections."In every country, elections are held only once, not like India where we have elections all the time. Due to this, I face a lot of problems as an MP when work stops due to the enforcement of the model code of conduct. If elections are held only once, then the money saved can be used for different purposes like education and health..," she said.

Earlier today, the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024' and 'The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024' was formally introduced in Lok Sabha after members voted on it.

The bill proposes a 'One Nation One Election' or simultaneous elections to both Lok Sabha and state assemblies. The bill will be sent to a Joint Parliamentary Committee (JPC) for detailed discussions.

The Speaker of the Lok Sabha announced the result of the vote on the introduction of the bill in the House. The vote showed 269 members in favor (Ayes) and 196 against (Noes).

This followed Law Minister Arjun Ram Meghwal's formal introduction of the Constitution (129th Amendment) Bill, 2024, on 'One Nation, One Election' and his agreement to send the bill to a JPC in response to Union Home Minister Amit Shah's statement.Meanwhile, Congress MP Manish Tewari opposed the move, arguing, "Beyond the seventh schedule of the Constitution is the basic structure doctrine, which spells out that there are certain features of the Constitution beyond the amending power of the House. The essential features are federalism and the structure of our democracy. Therefore, the bills moved by the Minister of Law and Justice are an absolute assault on the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of the House."

DMK MP TR Baalu opposed the bill, stating, "I oppose the 129th Constitution Amendment Bill, 2024. As my leader M.K. Stalin has said, it is anti-federal.

"Lot Of Hatred": Congress Demands Amit Shah's Apology For Ambedkar Remark

New Delhi. The Congress on Tuesday alleged that Home Minister Amit Shah's remarks in the Rajya Sabha during a debate on the Constitution show that the BJP and the RSS leaders have a "lot of hatred" for B R Ambedkar and demanded an apology from him.

Former Congress chief Rahul Gandhi said those who believe in Manusmriti will definitely be at odds with Ambedkar.Congress general secretary-in-charge communications Jairam Ramesh shared a video snippet on X from Mr Shah's speech in the upper house.Abhi ek fashion ho gaya hai - Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar. Itna naam agar bhagwan ka lete to saat janmon tak swarg mil jata (It has become a fashion to say Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar'. If they had taken God's name so many times, they would have got a place in heaven)," Mr Shah said, taking a swipe at the opposition.Mr Shah said the BJP is happy that the Congress is taking Ambedkar's name but the party should also speak about its real sentiments towards him. He pointed out how Ambedkar had to resign from the first Cabinet citing his disagreement with the then Congress-led government's policies including Article 370.Congress president Mallikarjun Kharge lashed out at Amit Shah, saying the "insult" of Babasaheb by the home minister "has once again proven that the BJP-RSS were against the tricolour, their forefathers opposed the Ashok Chakra and the people of the Sangh Parivar wanted to implement Manusmriti instead of the Constitution of India from the very first day"."Babasaheb Dr Ambedkar Ji did not allow this to happen, that is why there is so much hatred towards him,"

Mr Kharge said.

"The ministers of the Modi government should understand carefully that for crores of people like me, Babasaheb Ambedkar is no less than God... He is and will always be the messiah of Dalits, tribals, backward classes, minorities and the poor," Mr Kharge said in a post in Hindi on X.In a post on X, Mr Ramesh said, "Amit Shah has said something very disgusting. This shows that the BJP and RSS leaders have a lot of hatred for Baba Saheb Ambedkar." "The hatred is such that they are annoyed even by his name. These are the same people whose ancestors used to burn the effigies of Baba Saheb, who themselves used to talk about changing the Constitution given by Baba Saheb," the Congress leader said.

As the people taught them a lesson, they are now annoyed with those who take Baba Saheb's name, he said."Shameful! Amit Shah should apologise to the country for this," Mr Ramesh asserted.

Congress general secretary in-charge organisation K C Venugopal also hit out at Amit Shah over his remarks."HM Amit Shah, in case you didn't know - Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar is equivalent to God and the Constitution he drafted is a Holy Book for crores of people across the world. How dare you speak about Dr. Ambedkar with such disdain?" he said.

Delhi air quality remains 'severe', thick blanket of smog reduces visibility

▶Delhi weather: Of Delhi's 37 monitoring stations, 32 of them had AQI readings beyond the 400-mark, with the worst affected areas being Anand Vihar, Burari and Lajpat Nagar with AQI above 480.

New Delhi. Delhi-NCR residents on Wednesday woke up to a thick layer of smog as the air quality index (AQI) remained in the 'severe' category for the third consecutive day with an overall reading of 442.According to the India Meteorological Department (IMD), the temperature in certain areas of Delhi was above 7.6 degrees Celsius. The minimum temperature in Palam was recorded at 7.4 degrees Celsius, while in Lodhi Road, the minimum temperature was recorded at 8.4 degrees Celsius. Humidity levels fluctuated between 100 and 66 per cent during the day.

Delhi's 24-hour average Air Quality Index (AQI) was recorded at 442 (very poor) at 7 am on Wednesday. According to CPCB data, the Air Quality in 32 stations of Delhi were in the 'Severe' category, with Anand Vihar, Burari and Lajpat Nagar having an AQI above 480. In Jahangirpuri, the AQI was at 464, while in Vivek Vihar, the AQI was at 455, and in Rohini, the AQI was at 458. In Punjabi Bagh, the AQI was at 450.

Early morning visuals from the city showed a significant reduction in visibility. At the Delhi airport, low-visibility procedures were implemented after the visibility came down to 300 meters.

This is the third consecutive day when the air quality in Delhi remained in the 'Severe' category. On December 16, the authorities imposed GRAP-IV restrictions in a bid to curb worsening pollution levels.

The CPCB classifies AQI between 0 and 50 as "good", between 51 and 100 as "satisfactory", between 101 and 200 as "moderate", between 201 and 300 as "poor", between 301 and 400 as "very poor", and above 400 as "severe".The primary pollutant on Wednesday was PM2.5, with levels recorded over189.5 µg/m³ at 5 am. These fine particles pose significant health risks as they can penetrate deep into the lungs and enter the bloodstream.In the coming days, Delhi may witness a further increase in the cold wave with shallow fog in various parts due to calm winds and high humidity, as the IMD.

Meanwhile, the cold weather conditions persisted in many parts of north and east India on Wednesday, with minimum temperature in parts of Kashmir dropping several notches below freezing point.Earlier on Tuesday, Srinagar recorded a minimum temperature of minus 5.3 degrees Celsius, down from minus 3.4 degrees Celsius the previous night, with water supply lines in many parts of the city and elsewhere in the Valley getting frozen due to the cold.

NEWS BOX

US President-elect Trump says India charges a lot of tariff, threatens to impose reciprocal tax

WASHINGTON. US President-elect Donald Trump has reiterated his intention to impose reciprocal tariffs in retaliation for the 'high tariff' imposed by New Delhi on the import of certain American products.

"Reciprocal. If they tax us, we tax them the same amount. They tax us. We tax them. And they tax us. Almost in all cases, they're taxing us, and we haven't been taxing them,"Trump told reporters on Monday.

He made the remarks while responding to a question on a potential trade agreement with China.Trump said India and Brazil were among countries that impose high tariffs on certain US products.

"The word reciprocal is important. if India charges us 100 per cent, do we charge them nothing for the same? You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing," Trump said at a news conference at Mar-a-Lago.Responding to a question, his Commerce Secretary pick Howard Lutnick said reciprocity is something that is going to be a key topic for the Trump administration.

"How you treat us is how you should expect to be treated," he said.

The legal cases rankling Spain PM Pedro Sanchez

MADRID. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez is grappling with a series of legal probes involving his inner circle, including his wife, brother and former transport minister, that have tainted his leftist government.While the 52-year-old and his Socialist party have dismissed the cases as baseless and part of a right-wing "smear campaign", the judicial onslaught has given his opponents fresh ammunition to attack him.Here is a look at the legal cases facing one of Europe's longest-serving leaders:

Wife

Sanchez's wife, Begona Gomez, has been under investigation since April for alleged corruption and influence peddling related to her time working at Madrid's Complutense University following complaints from two groups with far-right ties -- "Manos Limpias" (Clean Hands) and "Hazte Oir" (Make Your Voice Heard).

She is also suspected of illegally appropriating software financed by private companies and initially intended for the universityThe 49-year-old was questioned by a judge in July and is scheduled to testify again on Wednesday at a Madrid court looking into the affair.

During an appearance before the conservative-controlled Madrid regional parliament in November, Gomez dismissed the corruption allegations as politically motivated.

Ex-minister

Sanchez's former transport minister Jose Luis Abalos, who used to be a member of his inner circle, is under investigation for allegedly having taken kickbacks for contracts to buy masks and other medical supplies in 2020 during the Covid-19 pandemic.According to a court document consulted by AFP, Abalos may have received "financial compensation" for his services in the form of a house in the southern city of Cadiz offered by the company that received the contracts.

The same company also allegedly paid the rent for a Madrid flat occupied by a woman "linked" to the former minister.

Israel's borders have shifted throughout its history, action in Syria may reshape them again

JERUSALEM. Israel's prime minister, Benjamin Netanyahu, entered Syrian territory Tuesday and said Israeli troops would remain in the area indefinitely, blurring the border with its northern neighbor.Since its establishment in 1948, Israel has never had fully recognized borders. Throughout its history, the frontiers with its Arab neighbors have shifted as a result of wars, annexations, ceasefires and peace agreements.Now, the downfall of Syrian President Bashar Assad has created a situation that could once again reshape Israel's borders.

As Assad was toppled early this month, Israel quickly moved into the Syrian side of a 50-year-old demilitarized buffer zone. Netanyahu described the move as defensive and temporary, and said it was aimed at making sure that none of the groups jostling for power inside Syria threatened Israel.

But in Tuesday's visit to the Syrian side of the buffer zone, Netanyahu made clear that Israel plans on staying for some time. Speaking on the windswept summit of Mount Hermon overlooking Syria, he said Israel would remain "until another arrangement is found that will ensure Israel's security."Here is a closer look at the evolution of Israel's borders over the years.

Israel's establishment

In 1947, the United Nations approved a plan to partition what was then British-controlled Mandatory Palestine into Jewish and Arab states. The contested city of Jerusalem was to be administered by the U.N.This plan, however, was never implemented. Israel declared independence in May 1948, and neighboring Arab countries declared war. That war ended with Israel in control of some 77% of the territory – with Jordan controlling the West Bank and east Jerusalem, and Egypt in control of the Gaza Strip.1967 Mideast warDuring the six days of fighting of the 1967 Mideast war, Israel captured the West Bank and east Jerusalem from Jordan, Gaza and the Sinai peninsula from Egypt, and the Golan Heights from Syria.Initially celebrated by Israel, the lightning victory set the stage for decades of conflict that continue to reverberate today.Israel quickly annexed east Jerusalem – home to the city's most sensitive Jewish, Muslim and Christian holy sites as well as its Palestinian population.

Biden admin makes it easier for US companies to hire foreign workers with H-1B visas

WASHINGTON. The outgoing Biden administration has relaxed rules for H-1B visas that will make it easier for American companies to hire foreign workers with special skills and facilitate a smoother transition from F-1 student visas to H-1B visas, a move that is likely to benefit thousands of Indian tech professionals.

The most sought-after H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in speciality occupations that require theoretical or technical expertise.Technology companies depend on it to hire tens of thousands of employees each year from countries like India and China.The rule, announced by the Department of Homeland Security (DHS) on Tuesday, aims to provide greater flexibility to employers and workers by modernising the definition and criteria for special positions and nonprofit and governmental research organisations that are exempt from the annual statutory limit on H-1B visas.The changes will help US employers hire as per their business needs and remain competitive in the global marketplace, an official release said.President-elect Donald Trump will take charge as the next president of the US after his swearing-in ceremony on January 20.According to the DHS, the rule also extends certain flexibilities for students on an F-1 visa seeking to change their status to H-1B to avoid disruptions in lawful status and employment authorisation for students holding F-1 visas.It also will allow US Citizenship and Immigration Services (USCIS) to process applications more quickly for most individuals who had previously been approved for an H1-B visa.It will also allow H1-B visa holders with a controlling interest in the petitioning organisation to be eligible for H-1B status subject to reasonable conditions.

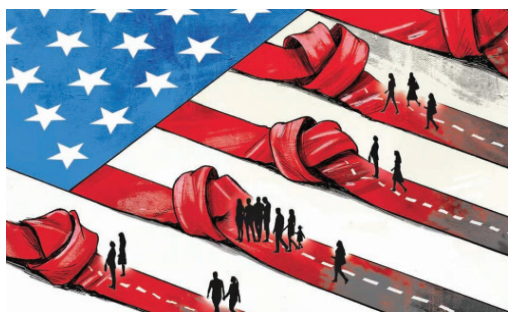

The latest move by the outgoing Biden administration builds on its previous efforts to ensure that the labour needs of American businesses are met to reduce undue burden on employers while adhering to all U.S.worker protections under the law.

"American businesses rely on the H-1B visa programme for the recruitment of highly-skilled talent, benefiting communities across the country,"said Secretary of Homeland Security Alejandro N. Mayorkas."These improvements to the programme provide employers with greater flexibility to hire global talent, boost our economic competitiveness, and allow highly skilled workers to continue to advance American innovation,"he said."The H-1B programme was created by Congress in 1990, and there's no question it needed to be modernised to support our nation's growing economy,"said USCIS Director Ur M.Jaddou.The changes made in the final rule will ensure that U.S.employers can hire highly skilled workers they need to grow and innovate while enhancing the integrity of the programme, he said.The DHS said the rule also strengthens the programme's integrity by codifying USCIS' authority to conduct inspections and impose penalties for failure to comply; requiring that the employer must establish that it has a bona fide position in a speciality occupation available for the worker as of the requested start date.It clarifies that the Labor Condition Application must support and properly correspond with the H-1B petition; and requires that the petitioner have a legal presence and be subject to legal processes in the courts of the United States.In order to implement the rule, a new edition of Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, will be required for all petitions beginning January 17, 2025, which is the rule's effective date.In order to implement the rule, a new edition of Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, will be required for all petitions beginning January 17, 2025, which is the rule's effective date.

At least 25 killed, dozens missing after overcrowded boat capsizes in Congo

KINSHASA. An overcrowded boat capsized on a river in central Congo on Tuesday, killing at least 25 people, including children, and leaving dozens missing, officials and local residents said.The vessel was believed to have more than 100 passengers on board after leaving from the town of Inongo, northeast of the capital of Kinshasa. It capsized a few hundred meters (yards) into the journey along the Fimi River, the latest such tragedy to strike Congo.

A search was underway for the missing hours later on Tuesday as concerns rose that the death toll could be far higher.

"There was overloading at roof level and, as far as the lifeless human bodies are concerned, at least 25 have been recovered so far," said David Kalemba, Inongo's river commissioner.The capsized boat was also loaded with goods, according to Alex Mbumba, a resident of the area. "Among the dead are children, but it's difficult to give an exact death toll at the moment as ... the boat had a lot of passengers," said Mbumba.Tuesday's wreck was the fourth this year in the Maï-Ndombe province, a region surrounded by rivers and where many rely on river transportation.Congolese officials have often warned against overloading

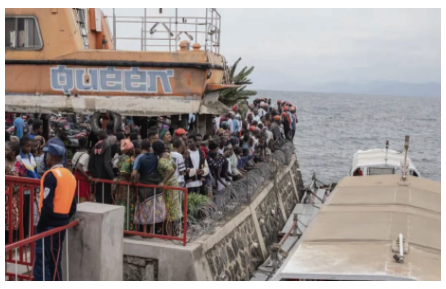

and vowed to punish those violating safety measures for water transportation.However, in remote areas where most passengers come from, many are unable to afford public transport for the few available roads.

At least 78 people drowned in October when an overloaded boat sank in the country's east while 80 lost their lives in a similar accident near Kinshasa in June.The latest accident prompted calls for the government to equip the province with flotation devices.

"The government must act to improve safety on the waters of our province (because) navigation conditions are dangerous," said Mbumba.The capsizing of overloaded boats is also becoming increasingly frequent in this central African nation as more people are abandoning the few available roads for wooden vessels crumbling under the weight of passengers and their goods because of security reasons.

The roads are often caught up in the deadly clashes between Congolese security forces and rebels that sometimes block major access routes. Hundreds have already been killed or declared missing in such accidents so far this year.

14 dead and hundreds injured after a magnitude 7.3 earthquake in Pacific nation of Vanuatu

WELLINGTON. At least 14 people are dead and hundreds more are injured after a magnitude 7.3 earthquake struck off Vanuatu on Tuesday, causing widespread damage across the South Pacific island nation. Rescuers worked through the night trying to reach some people yelling under the rubble.

The Red Cross reported the toll early Wednesday, citing government sources. Widespread damage to communications and other infrastructure has impeded the release of official reports. Phone service remained down.The earthquake occurred just before 1 PM at a depth of 57 kilometers (35 miles) and was centred 30 kilometers west of Port Vila, the largest city in Vanuatu, a group of 80 islands home to about 330,000 people. A tsunami warning was called off less than two hours after the quake, which was followed by large aftershocks.More than 200 people have been injured, said Katie Greenwood, Fiji-based head of the Red Cross in the Pacific, in a post on X. Vanuatu's main hospital has been damaged and the water supply has been compromised, she added.The UN humanitarian office said access to the airport and sea port were "severely limited due to road damage," which could affect efforts to deliver aid.Residents were urged to stay away from coastlines for at least 24 hours, and until tsunami and earthquake monitoring systems were operational again.Some people are trapped

Social media videos showed rescue efforts through the night for people trapped in buildings, including a three-story structure that collapsed onto its lower floors.Amanda Laithwaite said her husband was among rescuers searching for eight people they could hear yelling inside, but their progress was slow.

Three people were pulled alive from rubble overnight, her husband, Michael Thompson, wrote on Facebook. In one video he shared, a dust-covered woman lay on a gurney. Army personnel and civilians worked with tools and shovels, Thompson said.

The country does not have capacity to cope with a mass casualty event, Vanuatu-based journalist Dan McGarry told The Associated Press. He had visited Vila Central Hospital, where video shared by the Vanuatu Broadcasting and Television Corporation showed crowds outside.

Doctors were working "as fast as they could" at a triage center outside the emergency ward, he said.

Embassies are damagedA building housing a number of diplomatic missions in Port Vila — including those of the United States, Britain, France and New Zealand — was significantly damaged.The U.S. Embassy's Facebook page said all staff were safe, but the building was closed until further notice. The office opened in July as part of a push by the U.S. to expand its Pacific presence to counter China's influence in the region.

New Zealand's foreign ministry said officials have accounted for all but two of its embassy staff. Australia's foreign ministry said its workers were safe.

State-backed changes to demographics and cultural identities keep tensions alive in post-war Sri Lanka

MULLAITIVU/ JAFFNA. In the Tamil-majority northern province of Sri Lanka, as a road turns uphill towards Old Chemmalai, near the scenic Nayaru Lagoon in Mullaitivu district, there stands a statue of Lord Buddha.The nation's Department of Archaeology now recognises this place as an ancient Buddhist site of significance. Adjacent to the statue stands the small Neeraviyadi Pillaiyar Kovil. Local Tamil-speaking Hindus say they have worshipped the Hindu deity here for generations.In recent years, this location has become a site of contested identities; the latest report of the Centre for Policy Alternatives (CPA), titled 'The Intersectional Trends of Land Conflicts in Sri Lanka,' terms this a sign of increasing "Sinhala-Buddhisisation" in the northern and eastern provinces, where large numbers of Sri Lankan Tamils and Muslims reside.Raja Chinnathambi, secretary of the Neeraviyadi Pillaiyar Kovil and resident of Chemmalai, claims the identity of the place has been altered since the final Eelam War when people of his village had to flee.

For generations, families from the village had access to land in Old Chemmalai, he says. This changed once the war ended in 2009. The Sri Lankan army has since set up a camp there, rendering a large part of that land inaccessible.

A board erected by the DoA at the contested religious site now prohibits many activities, including land clearing, logging, and cultivation.

The board installed by the Department of Archaeology in Sri Lanka, prohibiting various activities, near the Buddha statue that has come up at Old Chemmalai near Nayaru Lagoon in Mullaitivu district.The board installed by the Department of Archaeology in Sri Lanka, prohibiting various activities, near the Buddha statue that has come up at Old Chemmalai near Nayaru Lagoon in Mullaitivu district."Earlier, we had unfettered access to this land. We would graze cattle and pick forest produce. Now, even observing festivals at our temple has become difficult," he says. Local Tamil-speaking Hindus fought a long and intense battle -- on the ground and in the courts -- to retain their right to worship here.The changes in demography and cultural identity in many places, with the support of state agencies such as the DoA, are a major cause of ethnic tension, especially in the eastern province.Construction of new Buddhist temples in Kuchchaveli in the eastern district of Trincomalee and of a Buddhist place of worship in Kuruthurmalai in the northern district of Mullaitivu, which was traditionally used by Tamil-speaking Hindus to worship Athi Shivan Iyanar, are some of the widely-discussed instances of this phenomenon.Pointing out how the DoA focuses primarily on the discovery of "ancient" Buddhist sites, Mahendran Thiruvarangan, an academic from the University of Jaffna and member of the Jaffna People's Forum for Coexistence, says these decisions of these institutions are all made at Colombo."Maybe there is a history to a particular site. But they (the State agencies) don't want to think about how these sites undergo changes over a prolonged period of time, that they are fluid and there are overlapping identities.

NSA Doval holds talks with Chinese foreign minister Wang Yi on peace at borders, restoring ties

BEIJING. India and China's Special Representatives for the border mechanism, National Security Advisor Ajit Doval and Foreign Minister Wang Yi met here on Wednesday to discuss a range of issues, including management of peace and tranquillity along LAC and restoration of bilateral ties frozen for over four years due to the military standoff in eastern Ladakh.

Doval, who is heading the Indian delegation, arrived here on Tuesday to take part in the 23rd round of the Special Representatives' talks being held after a gap of five years.

The last meeting was held in 2019 in Delhi.

The talks began at 10 am China time.

The two officials were expected to discuss a range of issues to rebuild the bilateral ties following the October 21 agreement of disengagement and patrolling in eastern Ladakh between the two countries.

On Tuesday, China expressed optimism about the talks saying that it is ready to work with India to implement the commitments based on the common understandings reached between Prime Minister Narendra Modi and President Xi Jinping during their meeting at Kazan in Russia on the sidelines of the BRICS summit on October 24.China is prepared to settle differences with sincerity, Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian told a media briefing here when asked about the Special Representatives (SR) talks.China is ready to work with India to implement the important common understandings between the leaders of China and India, respect each other's core interests and major concerns, strengthen mutual trust through dialogue and communication, properly settle differences with sincerity and good faith, and bring bilateral relations back to the track of stable and healthy development as soon as possible, he said.

The two SRs will discuss the management of peace and tranquillity in the border areas and explore a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question, as agreed upon during the meeting of the two leaders in Kazan, the External Affairs Ministry said on Monday.

After the Modi-Xi meeting, which was their first after five years, External Affairs Minister S Jaishankar and his Chinese counterpart met on the sidelines of the G20 summit in Brazil followed by a meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on China-India Border Affairs (WMCC).The military standoff along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh began in May 2020 and was followed by a deadly clash at the Galwan Valley in June of that year resulting in a severe strain in ties between the two neighbours.Barring trade, relations between the two countries virtually came to a standstill. The face-off effectively ended following the completion of the disengagement process from the last two friction points of Demchok and Depsang under an agreement finalised on October 21.The SRs' meeting is regarded as significant as it is the first structured engagement between the two countries to restore relations.Constituted in 2003 to comprehensively address the vexed dispute of the India-China border spanning 3,488 km, the SRs mechanism over the years met 22 times.While success eluded it in resolving the boundary dispute, officials on both sides regard it as a very promising, useful and handy tool in addressing the recurring tensions between the two countries.

NEWS BOX

Rohit Sharma avoids Mohammed Shami question after Gabba draw: NCA should answer

New Delhi India captain Rohit Sharma humorously sidestepped questions about pacer Mohammed Shami's availability for the ongoing Border-Gavaskar Trophy, stating that only the National Cricket Academy (NCA) could provide clarity on his fitness. Following India's hard-fought draw in the third Test against Australia at the Gabba, speculation intensified regarding potential changes in India's bowling attack for the series' remainder.Shami's name has been a constant topic amongst Indian cricket fans, who are eager to see the experienced bowler join forces with Jasprit Bumrah and Mohammed Siraj. However, lingering concerns over Shami's recovery from an ankle surgery in November 2023 have left the Indian management cautious. Addressing the media post-match, Rohit emphasised that the NCA would need to certify Shami's readiness before any decision could be made about his inclusion in the Test squad."I think it's high time somebody from NCA talked about him. That's our national cricket academy where

he is rehabing. Those guys are the ones who need to come up and give us some kind of update. But look, I understand he's playing a lot of cricket back home, but there have been some complaints about his knee as well. The last thing you want is the player coming here and then pulling out in the middle of the game. You know what happens when that kind of thing happens," Rohit said.

"There's no way we want to take that chance unless we are like, not a hundred percent, 200 hundred percent sure. We're not going to take any risk. But yeah, like I said in the last press conference, the door is open. If those guys at the NCA feel that he's okay to go and recovered, and play, I will be happy to have him," he addedShami, currently at the NCA in Bengaluru, has declared himself available for the upcoming Vijay Hazare Trophy. This development has complicated the possibility of his joining the Indian Test squad in Australia anytime soon.

Shami since his return from injury

The veteran pacer has been out of international action since the ODI World Cup Final. Following surgery and an extensive rehabilitation program, Shami marked his competitive return in the Ranji Trophy after India's dismal 3-0 Test series whitewash against New Zealand. He also impressed in the Syed Mushtaq Ali Trophy, further fuelling calls for his inclusion in the ongoing Australia series.

Vinícius Júnior and Aitana Bonmati win FIFA best player of the year awards

DOHA. Real Madrid star Vinícius Júnior finally got his hands on a big global player award on Tuesday.Vinícius was named the men's player of the year at the FIFA's "The Best" awards, where Barcelona playmaker Aitana Bonmati continued to clean up in the prizes for women's soccer.The 24-year-old Vinícius was so disappointed to lose out to Manchester City midfielder Rodri for the Ballon d'Or in October that he and his Madrid team snubbed the ceremony in Paris in protest.This time Rodri ended up second to Vinícius by five points. The Brazil forward was at the FIFA ceremony to collect his award having travelled to Doha on Monday with Madrid for the Intercontinental Cup final against Pachuca."I don't even know where to begin," Vinícius said in Portuguese. "It was so far away that it seemed impossible to get here. I was a kid who only played

football barefoot on the streets of São Gonçalo, close to poverty and crime.

"Getting here is something very important to me. I'm doing it for many children who think that everything is impossible and who think they can't get here."Vinícius echoed those sentiments in an Instagram post, where he took a thinly-disguised dig at presumably the Ballon d'Or voters — journalists from the top 100 countries in the FIFA rankings."Today I am writing to that boy who saw so many idols lift this trophy... your time has come," he wrote. "Or rather, my time has come. The time to say ... yes, I am the best player in the world and I fought hard for it."They tried and still try to invalidate me, to diminish me. But they are not prepared. No one is going to tell me who I should fight for, how I should behave."Vinícius has been subjected to racist abuse in Spain and at one point earlier this year said he was "losing my desire to play" but added "I'll keep fighting."Bonmati won the award for best women's player of the year making it back-to-back prizes.

There was not going to be an opportunity for Rana to start in our 11: Gujarat coach Klinger

Gujarat Giants coach shed light on some additions and some omissions ahead of the third season of Women's Premier League.

CHENNAI. Gujarat Giants, after finishing last in the back-to-back Women's Premier League points table, went into the mini-auction looking to make a few important changes.In an exclusive interaction with TNIE, the Australian coach Michael Klinger explained the auction strategies, hopes for his players and future plans. Excerpt...

On acquiring West Indies' Deandra Dottin

She was definitely our target in that first set for a few reasons. She's a match winner. She brings power to our batting lineup and she can bowl four quality overs for us, especially through the middle and death and she's such a versatile player and a match winner and she's been part of championship teams recently and, and that's what we were after.

I watched her closely recently in the WBBL. She is someone who we're excited to have with us.

On retaining Sayali Satghare in the squad

With Sayali, I suppose it's unusual for a team to bring in a replacement last year. She didn't get a game for us, but we retained her. Her performance in domestic cricket has been fantastic. She bowls during difficult period, she bowls in the power play, she bowls at the death. She bats in the top six in domestic cricket. So we know she can give us some useful runs if required.We know she can add a value in the batting area as well. So we had a camp recently with our local players and she was outstanding there as well. With the ball and her execution when we tried to put a bit of extra pressure on and set scenarios was fantastic. We are really looking forward to having her in the squad and no doubt she'll win some matches for us this year.

On breaking bank for Simran Shaikh

Leading into the auction, we probably didn't think she would go that high but she was a player of interest for us in particular because of her power and the strike rate that she batted at in the recent Challenger Trophy. Her strike rate was over 200. That's very rare in women's cricket.We feel that we have a local batting group who can play a very similar way to probably a lot of the other batters that were available. So we were looking at someone different and someone

who could bring power to our squad and she was that player.She's had a taste of WPL in season one with UP. We're really excited to have her here and feel that she can win some matches for us with a style about it.

On not picking former Giants captain Sneh Rana

When we were strategising around the players we were looking to retain, there was a clear strategy to pick players who we thought would have the chance of starting in our 11. With us having Ashleigh Gardner as our main offspinner and then two good left unorthodox in Mannat Kashyap, Tanuja Kanwar and of course with Priya Mishra, there was just not going to be an opportunity for her to start in our 11. And Sneh just didn't quite fit that, but it was a really tough decision because she is a high quality player, I think when we made that decision, it was just after she got 10 wickets in a Test match.

She's not in the Indian white-ball squads either. She's a very good white ball player, I was pretty confident she would get picked up elsewhere and get an opportunity maybe to play elsewhere. It hasn't turned out that way for her. It was great to have her around the group.

On England's Danielle Gibson

I think she's a high quality player. We were very lucky to get her at base price. Probably what helped us with that is she has been injured the last few weeks but she's back playing now.

hat probably helped not having other people bidding for her, but she adds a huge amount of versatility for us. She's a fantastic bowler combined in all phases and can bowl very well at the depth one of the best fielders in the women's game and a power hitter.

On Prakashika Naik getting a nod

Prakashika Naik is another leg spinner who's probably been the best performing leg spinner in domestic game, especially the Challenger Trophy. We have Priya Mishra who's going great with India at the moment, but maybe on occasion when we decide to play two leg spinners if conditions suit.

They're gold dust in men's or women's cricket if you get the right conditions and have two high-quality leg spinners in the team.

R Ashwin retires: Nothing but respect for him, says Australia's Nathan Lyon

New Delhi. Australia off-spinner Nathan Lyon paid a rich tribute to R Ashwin after the Indian spin maestro announced his retirement from all forms of international cricket on Wednesday. Lyon said he had "nothing but respect" for Ashwin and hailed his skillset as "incredible."Speaking to reporters after the Brisbane Test, which ended in a draw, Ashwin revealed that Wednesday would be his last day representing India in all formats. Widely regarded as one of the greatest off-spinners in Indian cricket history, Ashwin served the national team with distinction. Across all formats, he played 106 Tests, 116 ODIs, and 65 T20Is, taking a remarkable 775 wickets."Nothing but respect (for Ashwin). Just the way Ash has conducted himself on and off the field for a number of years now, and his skill set is incredible. We've got different opinions on different things, there's no right or wrong. But to have those conversations with a bowler like Ashwin is amazing," Lyon said while speaking to Fox Cricket.Earlier in the day, the Indian spinner spent considerable time talking with Lyon. Lyon said the duo spoke about 'different variations, different tactics and understanding what he's trying to do'. "We are both very different. So our conversation this morning was brilliant and I hope we

have more through the series and in the future as well," Lyon said.

Ashwin, who played in the Adelaide Test, had to make way for Ravindra Jadeja in the third match of the Border-Gavaskar Trophy. India used three different spinners in the first three Tests of the series, with the team management opting for Washington Sundar in the opening Test in Perth.Asked about this, Lyon told the Australian broadcaster: "It's an interesting question. You've got someone sitting [on the bench] with 530-odd Test wickets and I'm walking to the ground, scratching my head, saying 'What are you doing?'. He's proven that he is one of the world's best spin bowlers to ever play the game." Ashwin's retirement comes in the middle of the India vs Australia Test series. He played just one Test in the ongoing Border-Gavaskar Trophy. He was named in the playing XI for the second Test in Adelaide, which Australia won by ten wickets. In the match, Ashwin took just one wicket and recorded scores of 22 and 7. Ashwin has long served Indian cricket and is inarguably one of the greatest off-spinners the country has ever produced. He played 106 Tests, 116 ODIs, and 65 T20Is for India, taking 775 wickets across all formats.In Tests, Ashwin has claimed his wickets at an impressive average of 24 and a strike rate of 50.7, including 37 five-wicket hauls. His achievements extend far beyond these figures. Ashwin retires as the seventh-highest wicket-taker in Test history and holds the distinction of being the highest wicket-taking off-spinner in the format. However, Nathan Lyon is expected to surpass this record in the future.Lyon said he expected Ashwin to play in Melbourne and Sydney. However, Ashwin called time on his career later in the day. "[It] more than surprises me (that Ashwin didn't play).

Virat Kohli reacts to R Ashwin retirement: When you told me, it made me emotional

Former captain Virat Kohli said R Ashwin made him emotional when he told him about his decision to retire. In a heartwarming post on social media, Kohli paid tribute to the most successful Indian off-spinner, wishing him the best for his post-retirement career.

Virat Kohli highlighted R Ashwin's match-winning contributions in Test cricket and said the off-spinner would be 'remembered as a legend of Indian cricket'.Ashwin retired from international cricket on Wednesday, minutes after the third Test of the Border-Gavaskar Trophy ended in a rain-affected draw."I have played with you for 14 years and when you told me today you're retiring, it made me a bit emotional and the flashbacks of all those years playing together came to me. I've enjoyed every bit of the journey with you ash, your skill and match-winning contributions to Indian cricket are second to none and you will

always and always be remembered as a legend of Indian cricket," Virat Kohli said in his post."Wish you nothing but the best in your life with your family and everything else that it unfolds for you. With massive respect and lots of love to you and your close ones. Thanks for everything buddy," he addedVirat Kohli and R Ashwin shared a warm embrace during a rain interruption in the dressing room at Gabba, Brisbane on Wednesday, December 18. Ashwin and Kohli were engaged in an intense chat on Day 5 of the third Test, leading to retirement rumours.Ashwin ensured the rumours did not stay long as he announced his retirement from all formats of international cricket right after the end of the third Test. Ashwin attended the press conference along with India captain Rohit Sharma to confirm his decision.R Ashwin's rose to the pinnacle of Test cricket came under Virat Kohli's captaincy. He picked up 293 wickets in 55 Tests, including 21 five-wicket hauls.

Ashwin played an integral role in India's home series dominance during Virat Kohli's era as captain between 2014 and 2021.

Ashwin was named the ICC Cricketer of the Year and ICC Test Cricketer of the Year in 2016, becoming only the third Indian to win the Sir Garfield Sobers Trophy for his remarkable all-round performances that year.

Gabba Test: Convinced R Ashwin to stay for pink-ball Test, reveals Rohit Sharma

New Delhi. India captain Rohit Sharma has revealed that he asked R Ashwin to stay on for the pink-ball Test after the spinner announced his retirement from the game after the match in Gabba. Ashwin, who played the game in Adelaide, wasn't picked in the side for the matches in Perth and Brisbane.After a glorious career, Ashwin decided to announce during the post-match press conference that he has retired from international cricket completely. Speaking about the retiring spinner, Rohit revealed that he came to know about Ashwin's decision when he had arrived in Perth. The India captain revealed that Ashwin understood the team's plans and the combinations they would be going with and hence decided to make the call after the match in Brisbane."I heard R Ashwin's

retirement when I came to Perth. I was not there for the first few days of the Test. This was in his mind since then. There are obviously a lot of things that went behind it. Ashwin, when he is in position, will be able to answer that. He understands the kind of combinations we are thinking. When we came here as well, we were not sure which spinner was going to play. We just wanted to assess and see what kind of conditions we get in front of us. But yeah, when I arrived in Perth, we had a chat and somehow convinced him to stay for the pink-ball Test match. It happened so that he felt 'if I am not needed right now in the series, then I am better off saying goodbye to the game.

"Keeping Ashwin in mind, if this is what he thinks, we should allow him to think that way. We should all standby his call. That is what I am thinking right now and that's the same mindset of Gautam Gambhir as well. It's important a player like him who has had great moments with the team is allowed to make such a call," said Rohit during the press conference.

R Ashwin retires: Sunil Gavaskar criticises timing of spinner's unforeseen call

Sunil Gavaskar was critical of R Ashwin's decision to retire from all formats of the game midway through the Border-Gavaskar Trophy on Wednesday, December 18. Ashwin made the decision right after the Gabba Test ended in a draw.

New Delhi. Sunil Gavaskar has been critical of the timing of R Ashwin's retirement call, claiming that the spinner should have made the decision after the end of the Border-Gavaskar Trophy. Ashwin would make the shock call after the Gabba Test on Wednesday, December 18, after the match ended in a draw.

The rumours had started to come in on Wednesday morning when Ashwin was seen sharing a warm embrace with Virat Kohli in the dressing room as the game was halted by rain. Ashwin would then appear alongside Rohit Sharma in the post-match press conference and announce his decision to the reporters. Speaking to the broadcasters, Gavaskar said that the shock call had now left the Indian squad one man short. The Indian legend feels that Ashwin could have had a chance to make it to the side during the Sydney, where the pitch could have offered support to spinners.He could have said, listen after the end of the series, I won't be available for selection for India. What it does is that, similarly when MS Dhoni retired at the end of the 3rd Test in 2014-15 series, it leaves

you one short. The selection committee has picked so many players for a tour with a purpose. If there are any injuries they can select from the reserve players to have in the team. So, Sydney is somewhere where there is a lot of support on offer for spinners. So India could have played with 2 spinners. You never know. He could have been there for sure. I don't know how the pitch in Melbourne will be like."Normally, you tend to look at the end of the series. That's it. In the middle, it is not usual," said Gavaskar.When asked if Washington Sundar was ahead of Ashwin in the pecking order, Gavaskar said that could be the case. The Indian legend ended by hailing Ashwin as a fine cricketer."Maybe Washington Sundar is ahead of him. Rohit said he is flying out tomorrow. So that's the end of Ashwin as an international cricketer. He has been one heck of a cricketer," said Gavaskar.

Nothing Just

Shraddha Kapoor

Making Our Day With Her Infectious Smile

Shraddha Kapoor is undoubtedly one of the most adored actresses in Bollywood. Apart from her acting prowess, she is also known for her sense of fashion. The diva often treats her Insta fam with her glamourous pictures and videos. For her recent Instagram outing, the Aashiqui 2 actress opted for a black and white peplum t and matching pleated skirt. “Early 2000s ke kaunse gaane sabse best hai ???," the post caption reads.

The actress dropped a phot dump of her stunning outfit that she opted for a recent event. The first picture is a selfie wherein Shraddha is seen sporting a minimal makeup look and flaunting her adorable smile.

The next snapshot features a close-up shot of the actress in which she is seen flaunting her silky tresses open As soon as the pictures were shared online, fans and admirers were quick to share their reactions to it. An Instagram user wrote, “Is it allowed to be this muc pretty huh??" Another person added, “Looking just The Ek Villain actress recently attended the Red Sea Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia. On the red carpet, she was seen posing along with The Amazing Spider-Man fame actor Andrew Garfield. Several pictures and videos of Shraddha with Andrew also went viral.During a chat with Pinkvilla, the Hollywood star showered praises on the Baaghi actress and said, “We had a lovely and very brief meeting on the red On the work front, Shra ddha Kapoor was last seen in the horror comedy film Stree 2: Sarkate Ka Aatank. Helmed by Amar Kaushik, the film also featured RajKummar Rao, Abhishek Banerjee, Aparshakti Khurrana and Pankaj Tripathi in lead roles.

Ranveer Singh

REACTS As Paparazzi Ask Him About Daughter Dua: 'Kab Mila Rahe Ho?'

Ranveer Singh and Deepika Padukone welcomed their first child daughter Dua in September this year. The couple has been enjoying their parenthood journey. Recently,Ranveer Singhwas spotted at the airport and had a heartwarming moment with Paparazzi. They asked him about his daughter Dua.In the video,

shared by Varinder Chawla, we can see Ranveer walking outside the airport. Paps cheekily asked, “Dua se kab mila rahe ho?". However, Ranveer did not respond and just smiled. He showed thumbs up while sitting inside the car. Fans too reacted. Fans dropped heart emojis in the comment section. Recently, Deepika was also spotted Deepika and her daughter Dua were spotted at the Mumbai airport in afternoon. Although Dua was all covered up, the cameras spotted her little hands. Deepika and Dua were spotted just days after she was seen at Diljit Dosanjh’s concert. Deepika was seen wearing a red outfit and styled her hair into a neat bun. She opted for a pair of chic sunglasses. She had Dua all covered up. However, her tiny hands were seen. Dua appeared to be asleep as they landed in the city.

Ranveer Singh, who was last seen in Singham Again, has sparked curiosity among fans as he shared photos with filmmaker Aditya Dhar. Both are seen visiting the Golden Temple in Amritsar. Looks like they are commencing the next schedule of their highly anticipated film in the city. Nothing As reported, the actor-director duo wanted to visit the Temple before starting the next schedule of the film. The team shot for an elaborate schedule in Bangkok earlier and this will be their second sThis year in July, Ranveer shared the big news on his Instagram handle. Sharing pictures with co-stars Sanjay Dutt, R. Madhavan, Akshaye Khanna and Arjun Rampal, Ranveer said, “This one is for my fans, who have been so patient with me, and been clamouring for a turn like this. I love you all, and I promise you, this time, a cinematic experience like never before. With your blessings, we embark on this great, big motion picture adventure with spirited energy and pure intent. This time, it’s personal."

Deven Bhojani And Prachee Shah Paandya's Udan Chhoo Makes Its OTT Debut

Bringing the unconventional story of a Gujarati family, Deven Bhojani and Prachee Shah Paandya starrer Udan Chhoo has finally premiered on OTT, months after its theatrical release. Directed by Anish Shah, Udan Chhoo has exclusively premiered on ShemarooMe on December 12, 2024, setting just the right mood for a family viewing experience. Bring to the fore an uncommon love story, the film also has a perfect mix of humour and emotional depth, which makes it even more special. It tells the story of Hasmukh Mehta, a single father searching for a match for his daughter Krina. Things take an interesting turn when Hasmukh unexpectedly crosses paths with his college sweetheart, Pankor, who is now a successful entrepreneur. Ironically, Pankor is also the mother of the potential groom, whom Hasmukh is considering for his daughter. The unique narrative changes the traditional matchmaking process into a chaotic journey, marked by rekindled romance and Keeping it light-hearted, the film explores the themes of second chances at love and the challenges amid societal norms, bringing a fresh and uniqu addition to contemporary Gujarati cinema.Additionally, actors like Deven Bhojani and Prachee Shah Paandya take on the lead roles as Hasmukh Mehta and Pankor, followed by Aarohi Patel, Aarjav Trivedi, Alisha Prajapati, Naman Gor, Pratik Nanda, and Sohni Bhatt who also deliver notable performances. The exceptional casting, with fresh pairings, brings a heartwarming story to life, making anho a must-watch for all generations.

Deven Bhojani, known for his work in shows like Sarabhai vs Sarabhai, Shrimaan Shrimati, Baa Bahu Aur Baby, and Dekh Bhai Dekh among others, expressed his excitement about the Udan Chhoo’s digital release. Stating that his characte of Hasmukh is a wonderfully layered person, he added, “Working with Anish Shah, who brings such a fresh and genuine vision, has been an absolute joy. The way the film balances nostalgia with modernity makes it relatable across generations," as per medianews4u.

Juhi Parmar Shares How Daughter Samairra’s, Family Made Her Birthday Special

Juhi Parmar is a proud mother of a daughter – Samairra’s Parmar. Previously married to Sachin Shroff, the actress shares the daughter with her former husband and they have been co-parenting their little bundle of joy despite the separation. Known for her iconic role in the TV show Kumkum – Ek Pyara Sa Bandhan and her recent role in the web series Yeh Meri Family, Parmar sat down for an interview, reflecting on how her family, particularly her daughter, makes it extra special for her on her Speaking with ETimes, Juhi Parmar shared, “My birthday celebrations are usually quite low-key. While I do host get-togethers at times, most of my birthdays are spent with my family and my close friends." Talking about the thoughtful surprises that her daughter treats her to, she added, “My daughter and my parents are the greatest blessings in my life. Their presence makes every day special, not just my birthday. Samairra’s, my daughter, always goes out of her way to make my birthday memorable. She creates adorable handmade cards and leaves sweet nJuhi Parmar also recalled the heartwarming srprise she received on her birthday last year. She took a trip down memory lane andrevealed, “I wasn’t home at midnight, but when I returned, I found that she had decorated my entire room with balloons and a lovely irtday message. She ven left a heartfelt card. Though shehad gone tosleep bythen, she had told my mom to wake her up when I got home. So she woke up, wished me, and then went back to Juhi Parmar rose to stardom in 2002 after portraying the lead character in the popular television series, Kumkum – Ek Pyara Sa Bandhan. This character made her a household name, garnering her immense popularity and love. Recently, the actress alo forayed into the OTT platforms, making her debut with the comedy family drama Yeh Meri Family 2. Created by Sameer Saxena, the OTT series also starred Hetal Gada, Anngad Raaj and Rajesh Kumar in lead roles.Juhi Parmar got maried to actor Sachin Shroff. Years after the marital bliss, the couple got divorced in 2018. She is now happily leading a life as a single mother.sleep."